नीति निर्माताओं के लिए तत्काल गाईड

एशियाई शहरों में गरीबों के लिए आवास

UNITED NATIONS ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

6

समुदाय–आधारित संगठन: गरीब, विकास के एजेंट के रूप में

सर्वाधिकार सुरक्षित © युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सैट्लमेण्ट्स प्रोग्राम एण्ड
युनाइटेड नेशन्स इकनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड द पैसिफिक, 2008

ISBN 978-92-113-1945-3
एच.एस./958/08 ई एशियाई शहरों में गरीबों के लिए आवास तत्काल गाईड–6

उत्तरदायित्व निषेध

इस प्रकाशन में किसी देश की वैधानिक स्थिति, क्षेत्र, शहर, उनके अधिकारियों अथवा उनकी आर्थिक व्यवस्था या विकास की कोटि से सम्बन्धित या इसकी सीमाओं के परिसीमन से सम्बन्धित कोई सामग्री अथवा प्रयुक्त उल्लेख किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विचार नहीं हैं। इस प्रकाशन में प्रस्तुत विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशों से युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सैट्लमेण्ट्स प्रोग्राम (यूएन हैबीटैट) अथवा इसकी गवर्निंग कौंसिल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। स्त्रोत दर्शाने पर इसके किसी भी अंश को बिना किसी अनुमति के उद्धृत किया जा सकता है।

आवरण सज्जाः टाम केर, एसीएचआर एव संयुक्त राश्ट्र के नैरोबी स्थित कार्यालय द्वारा प्रकाषित तथा नैरोबी में मुद्रित

आवरण चित्रः एशियन कोलिशन फॉर हाऊसिंग राईट्स

एशियाई शहरों में गरीबों के लिए आवास श्रृंखला का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हालैण्ड की सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के विकास खाते से दी गई वित्तीय सहायता द्वारा सम्भव हो पाया है

Cities Alliance
Cities Without Slums

'एशियाई शहरों में गरीबों के लिए आवास' तत्काल गाईडों की श्रृंखला का हिन्दी भाषा में रूपान्तरण एवं प्रकाशन सिटीज़ एलायन्स के वित्तीय सहयोग के माध्यम से सम्भव हो पाया है।

प्रकाशनः
युनाइटेड नेशन्स इकनामिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पैसिफिक (यूएन एस्कैप)
राजदमनेरन नोक एवेन्यू,
बैंकाक–10200, थाईलैण्ड
फैक्सः (66–2) 288 1056/1097
ई.मेलः escap-prs@un.org
वेबः www.unescap.org

एवं

युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सैट्लमेण्ट्स प्रोग्राम (यूएन हैबीटैट)
पो0आ0 बाक्स 30030 जी.पी.ओ. 00100
नैरोबी, केन्या
फैक्सः (254–20) 7623092
ई.मेलः tcbb@un-habitat.org
वेबः www.un-habitat.org

आभार

सात तत्काल गाईडों का यह सेट यू एन एस्कैप द्वारा जुलाई 2005 में थाईलैण्ड में शहरी गरीबों के आवास हेतु क्षमता निर्माण पर आयोजित विशेषज्ञ समूह की मीटिंग के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया है। इनको यूएन एस्कैप के 'गरीबी और विकास अनुभाग' तथा यूएन हैबीटैट की 'प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शाखा' (टीसीबीबी) द्वारा संयुक्त रूप से 'शहरी अर्थव्यवस्थाओं में गरीबों के लिए आवास' तथा 'बेहतर स्थानीय शासन और शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना' की परियोजनाओं के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के विकास खाते एवं डच सरकार द्वारा प्रदत कोष से तैयार किया गया। इसी सहयोग के अन्तर्गत प्रत्येक तत्काल गाईड के प्रमुख सन्देशों को उजागर करते पोस्टरों का एक सेट और स्व संचालित आन–लाईन प्रशिक्षण माड्यूल का एक सेट भी साथ ही विकसित किया जा रहा है।

तत्काल गाईडें श्री अदनान एलियानी, गरीबी और विकास अनुभाग, यूएन एस्कैप, और सुश्री ओसा जॉनसन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शाखा, यूएन हैबीटैट के व्यापक समन्वय एवं श्री याप कियो शेंग, श्री राफ टट्स और सुश्री नटालया व्हेमर के महत्वपूर्ण सहयोग एवं निवेश से तैयार की गई हैं। सुश्री क्लैरिसा अगस्टीन्स, श्री जीन–यवेस बारसीलो, श्री सेलमन अर्गुडन, श्री सोलोमन हेल, श्री जान मयूविसेन, श्री रासमस प्रेश्त, सुश्री लोई रोल्स और श्री जिंग झांग द्वारा भी अन्तः पुनरीक्षण एवं योगदान प्रदान किया गया।

गाइडें श्री थामस ए. केर; एशियन कोलिशन फार हाऊसिंग राइट्स (एसीएचआर) द्वारा श्री बाबर मुमताज, श्री माइकल मैटिंगली तथा पूर्व में यूनिवर्सिटी कालिज ऑफ लन्दन की विकास नियोजन इकाई से जुड़े श्री पैट्रिक वेकले; श्री याप कियो शेंग, यूएन एस्कैप; श्री अमन मेहता, सिनक्लेयर नाईट मर्ज कन्सलटिंग, श्री पीटर स्वैन, एशियन कोलिशन फार हाऊसिंग राइट्स; श्री कोइन डेवानडेलर, किंग मांगकुट एशियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी; थाईलैण्ड द्वारा तैयार प्रपत्रों के आधार पर तैयार की गई है।

मूल पत्रों तथा अन्य सामग्री को www.housing-the-urban-poor.net पर प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त योगदान ने तत्काल गाईडों की श्रृंखला को आकार दिया है और हमें आशा है कि ये एशिया में शहरी गरीबों के लिए आवास के सुधार की तलाश में जुटे नीति निर्माताओं के दैनिक कार्य में अपना योगदान प्रदान करेंगी।

विषय–सूची

परिस्थितियां

गरीब समुदाय : एशियाई शहरों का छिपा हुआ संसाधन 2
आत्म–निर्भरता का लंबा इतिहास.....3
समुदाय संगठन : असली एवं नकली 4
बहुआयामी दृष्टिकोण रखना 5

संकल्पनाएं

विरोध से वार्ता और प्रतिरोध से सहयोग की ओर 6
समुदाय संगठनों का नारा : ''हम अपनी बात खुद कह सकते हैं'' 7
समुदाय भागीदारी : पूर्ण स्वामित्व से समझौते की ओर 8

उपागम

भागीदारी : 7 तरीके जिनसे, 'गरीब समुदाय संगठन', एशियाई शहरों में भूमि, आवासीय, बुनियादी सेवाएं एवं गरीबी संबंधी समस्याओं को हल करने में अपनी सरकारों की सहायता कर रहे हैं.....9
आवासीय मामलों में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी.....10
पुनर्वास में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी..... 12
अपग्रेडिंग में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी.....14
आवासीय वित्त में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी 16
स्वच्छता में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी.....18
इन्फ्रास्ट्रक्चर में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी.....20
आपदा पुनर्वास में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी.....22

साधन एवं दिशानिर्देश

6 साधन जिनका प्रयोग समुदाय अपने संगठनों के निर्माण के लिए करते हैं.....24
समुदाय विकास निधियाँ.....34
समुदाय संगठनों को सहयोग देने के 10 तरीके.....36

स्त्रोत

पुस्तकें, लेख, प्रकाशन एवं वेबसाइट्स.....37

यह बेहद ज़रूरी है कि मुख्य समूह के रूप में सामाजिक न्याय की माँग करने वाले गरीब समुदाय, आने वाले समय में, अपनी विकास प्रक्रिया की देखरेख एवं संभाल स्वयं करें और अपने उत्थान एवं विस्तार में अहम भूमिका निभाएँ।

शीला पटेल, स्पार्क, इंडिया

चित्र: स्पार्क

समुदाय–आधारित संगठन: गरीब, विकास के एजेंट के रूप में

नीति निर्माताओं हेतु तत्काल गाईड संख्या 6

एशिया में गरीब व्यक्तियों के समुदाय संगठनों की उत्पत्ति, पिछले दो दशकों के दौरान बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभरी है। क्योंकि अब ऐसी संरचना विद्यमान है जिससे गरीब परिवार एवं गरीब समुदाय अपने अलग–थलग जीवन एवं असहाय होने से बाहर निकल कर सामूहिक शक्ति की ओर जा सकते हैं। इसलिए, गरीबों के ऐसे प्रयासों से गठित ये संगठन इन गरीबों के अपने देशों में शक्तिशाली विकास तंत्र बन गए हैं और हर नज़रिए से लोगों के अपने संगठन हैं।

इन संगठनों के माध्यम से न सिर्फ विचारों के आदान–प्रदान, परिसंपत्तियों के एकत्रीकरण और आपसी सहयोग की ही प्राप्ति होती है बल्कि ऐसे संगठन गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसे चैनलों की भी सृजना करते हैं जिनके माध्यम से ये अपनी स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकारों से बातचीत कर पाते हैं और आवासीय, अपग्रेडिंग, भू–धारणाधिकार, बुनियादी ढाँचे और आजीविका अर्जन जैसे मुद्दों पर आधारित सहयोगपरक विकास परियोजनाओं को भी आरंभ कर सकते हैं। एशिया के गरीब समुदाय, अन्य विकासपरक स्टेकहोल्डर्स संस्थानों के सहयोग से आवासीय एवं समुदाय संबंधी सुधारों को दर्शा रहे हैं।

समुदाय संगठन बेहद महत्वपूर्ण संसाधन संपन्न भागीदार हो सकते हैं विशेष रूप से जब इनकी परख गरीबों के लिए लाभप्रद आवासीय विकल्पों की खोज करने के परिप्रेक्ष्य से की जाये। गरीबों की निजी आवासीय समस्याओं का हल खोजने में, समुदाय संगठनों की भूमिका अनिवार्यतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यह समझना कि ऐसे संगठन कैसे विकसित होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और किन साधनों का प्रयोग करते हैं अर्थात ये सभी बातें निरंतर बढ़ते विकेंद्रीकरण के संदर्भ में नीतिनिर्माताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। यह गाइड एशिया के समुदाय संगठनों के इन पहलुओं पर प्रकाश डालती है।

यह गाईड विशेषज्ञों के लिए नहीं है अपितु इसका उद्देश्य उन राष्ट्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों एवं नीतिनिर्माताओं की क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना है जिन्हें न्यून आय संबंधी आवासीय मुद्दों पर अपनी समझ को तत्काल बढ़ाने की जरूरत है।

चित्रः यूएन एस्केप

"एक बात जो हमने कई वर्षों के अनुभव से सीखी है कि न तो दुर्भाग्य और निराशा और न ही नकारात्मक आलोचना; लोगों और सरकार को कार्रवाई करने हेतु प्रेरित करेगी। जो ज़रूरी है वह है सकारात्मक दृष्टिकोण और सुस्पष्ट विचार और पद्धति तथा व्यवस्था के प्रत्येक कार्यकर्ता को सौंपी गई स्पष्ट ज़िम्मेदारी"

– पूर्व यूएन सेकेट्री जनरल, कोफी अनान

गरीब समुदाय: एशियाई शहरों का छिपा हुआ संसाधन

शहरी गरीब, एशियाई शहरों में कम लागत से बने अधिकतर आवासों के डिज़ाइनर, निर्माता एवं आपूर्तिकार हैं। इनके स्व–सहायता प्रयासों ने वह किया है जो वर्षों से सरकारी आवासीय कार्यक्रम, औपचारिक क्षेत्र विकास परियोजनाएं, आवासीय अधिकार आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय विकास अंतःक्षेप नहीं कर पाये। अर्थात इनके स्व सहायता प्रयासों ने अधिकतर शहरी गरीबों को ऐसी कम कीमत पर रहने की जगह और बुनियादी सेवाएं, ऐसे इलाकों और व्यवस्था में उपलब्ध कराई हैं जो उनके सामर्थ्य में हैं तथा जिससे इनकी तात्कालिक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति तुरन्त तब होती है जब इन्हें इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत है, न कि दूर के भविष्य में।

गन्दी एवं अनौपचारिक बस्तियों में आवास एवं बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने वाली ये अनौपचारिक व्यवस्थाएं आदर्श किस्म की नहीं हैं और मुख्य रूप से 'गैरकानूनी' तथा कई तरीकों से प्रायः असमान और निम्न–स्तर की हैं। लेकिन जहाँ फिलहाल कोई विकल्प न हो वहाँ ये तत्कालिक आवश्यकता पर तुरंत ध्यान देती हैं। मानव संसाधन की संपन्नता के इस साक्ष्य से अभूतपूर्व स्वतंत्रता एवं स्व–जनित शक्ति की अनुभूति होती है और ये एशियाई देशों में अभी तक प्रयुक्त न की गई ऊर्जा के महान स्त्रोत हैं।

सरकार ऐसी अनौपचारिक बस्तियों को एक गंभीर समस्या मानती है जिन्हें शहरी भूमि पर किसी खतरे के संकेत या मवालियों के अड्डे या असामाजिक तत्वों के रूप में देखा जाता है और जिन्हें दण्ड देना आवश्यक है। लेकिन पिछले दो दशकों से, बहुत सी सरकारों एवं नीति निर्माताओं ने इन अनौपचारिक बस्तियों एवं इन्हें जन्म देने वाले समुदाय संगठनों को दूसरी निगाह से देखना शुरू किया है और ये सब अब इन समुदायों (और इनके संगठनों) की उस भूमिका को मान्यता दे रहे हैं जो ये शहरों में भूमि, आवासीय एवं आजीविका अर्जन से जुड़ी शहर–व्यापी समस्याओं का बड़े पैमाने पर स्थायी हल खोजने में निभा रहे हैं।

अधिकतर एशियाई शहरों की आवासीय परियोजनाएं असफलता का लम्बा एवं निराशापूर्ण इतिहास हैं। यही बात सामाजिक आवासीय विकास कार्यों पर भी लागू होती है जिसके फलस्वरूप अंत में गलत लक्ष्य समूह लाभान्वित हो जाते हैं। इसी तरह कई प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की गई जो आगे नहीं बढ़ पाईं। इसी तरह स्थल और सेवाएं योजना की भी शुरूआत हुई जहाँ कोई भी रहने का इच्छुक नहीं था और पुनर्वास परियोजनाओं को अटकलबाजों के भरोसे ही छोड़ दिया गया।

बहुत से सरकारी एवं आवासीय व्यावसायी अनुभव कर रहे हैं कि इन परियोजनाओं को उन गरीबों की भागीदारी के बिना ही तैयार किया गया था, जिनके लिए ये असल में बनी थी अर्थात् इनसे बढ़ती समस्याओं को हल नहीं किया जा सकेगा। वे यह भी अनुभव कर रहे हैं कि जब गरीब समुदाय संगठनों की खुद को प्रभावित करने वाली आवासीय एवं विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन में अहम् भूमिका होती है तो कार्यक्रमों के सफल होने की संभावना अधिक होती है।

आत्म निर्भरता का लंबा इतिहास

आत्मनिर्भरता ऐसे सभी पहलुओं की आधार बिंदु है जो इस बात से संबंधित है कि शहरी गरीब समुदायों को कैसे गठित किया जाता है और इनके निवासियों को बसने के लिए भूमि की प्राप्ति कैसे होती है, ये सभी जलापूर्ति एवं बिजली तक पहुँच कैसे स्थापित करते हैं, दुर्गम रास्तों से अपना रास्ता कैसे बनाते हैं, आपातकालीन स्थितियों में इन्हें ऋण कैसे मिलता है, इन्हें रोजगार की प्राप्ति कैसे होती है और ये ऐसे किसी शहर में अपनी गुजर–बसर कैसे करते हैं जहाँ इन्हें सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। गरीब बस्ती, जो किसी बाहरी व्यक्ति को उलझनपूर्ण नज़र आती है, असल में गरीबों के लिए समझौते, आपसी सहयोग, अंत:निर्भरता एवं निवासियों के संसाधनों को एकजुट बनाने का परिसर है।

यदि कोई अनौपचारिक समुदाय उसी जगह पर टिका रहता है और वर्षों तक ऐसी जगह को खाली भी नहीं कराया जाता तो संभव है कि वहाँ का समुदाय धीरे–धीरे बेहतर एवं समेकित रूप धारण कर लेगा और यहाँ की आवासीय एवं जीवन–यापन दशाओं में सुधार आएगा और इससे संबंधित सहयोग संरचनाएं और समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निपटान की सांझी व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जायेंगी। बहुत से समुदाय स्वयं को संगठित करने की क्षमताएं विकसित करते हैं और अन्य संगठनों को अपना सहयोग प्रदान करते हैं तथा बस्ती में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय राजनीतिज्ञों और सरकारी एजेंसियों से परिणामवादी संबंध विकसित करते हैं। इस तरह, समुदाय संगठन की शुरुआत होती है लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है।

एशियाई देशों में वर्ष 1960 और 1970 के दौरान बने अधिकतर समुदाय संगठन, स्थानीय अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों के किसी हस्तक्षेप या सहयोग के बिना गठित किए गए। दूसरी तरफ, अधिकतर स्थानीय अधिकारी, समुदाय संगठनों से समझौते की बातचीत करने से कतराते थे क्योंकि जमीन पर ''गैर कानूनी'' कब्जा करने वालों से यदि किसी भी प्रकार का सरकारी समझौता होता है तो इसे बस्ती में रहने वाले अपना कानूनी हक मानने लग जाते हैं। उन दिनों में ऐसी स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों की संख्या ज्यादा नहीं थी जो अपनी विविध सामाजिक या भौतिक विकास पहलों को लागू करने में गरीबों के सहयोग की प्राप्ति करने या गरीब समुदायों को सहायता देने की इच्छुक थीं।

फलस्वरूप, बस्तियों को कमोबेश अपने भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया गया और यदि इनके आवासीय या जीवन–यापन परिवेश में कोई सुधार हुआ भी तो यह पूर्णतया समुदायों के अपने सहयोग के फलस्वरूप ही हुआ और इस सुधार का, इनके लिए निर्मित वर्तमान कार्यक्रमों या सरकारी आवासीय एजेंसी के कार्यक्रमों से कोई सरोकार नहीं था।

चित्र: ल्यूमलि

जब–जब मनुष्यों को अपने साथी मनुष्यों का साथ मिला है, तो जीवित रहने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन सभी ने स्वयं को समुदायों में संगठित किया है क्योंकि इनमें से हर कोई अपनी शारीरिक, संवेगात्मक, आर्थिक, सुरक्षात्मक एवं सांस्कृतिक ज़रूरत को दूसरे के सहयोग के बिना अकेले पूरा नहीं कर सकता। यह सामूहिक आत्म–निर्भरता एशिया के शहरी गरीब समुदायों में आज भी जीवंत है।

चित्र: सीओडीआई

असल किस्म की समुदाय भागीदारी:

यदि परियोजना प्रबंधक अपनी विकास परियोजनाओं के सभी पहलुओं के माध्यम से विस्तृत एवं लचीले डिजाइन वाली, कार्यान्वयन कार्यनीतियों को अंगीकृत करते हैं तो नव–गठित समुदाय संगठन भी परियोजना के साथ–साथ वृद्धि कर सकते हैं, और ऐसे परिणाम निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त और सामाजिक दृष्टि से अधिक स्थायी होते हैं।

समुदाय संगठन: असली एवं नकली

समुदाय संगठनों और सरकारी आवासीय कार्यक्रमों के बीच अभूतपूर्व सहयोग के फलस्वरूप वर्ष 1970 और 1980 में कुछ महत्वपूर्ण सफल गाथाओं के उभरने से ''समुदायिक भागीदारी'' नामक नये शब्द की उत्पत्ति हुई। परिणामस्वरूप अधिकाधिक एशियाई विकासपरक परियोजनाओं को इस पूर्व–शर्त पर तैयार किया गया कि परियोजना में समुदाय संगठन अनिवार्यतया भागीदार होंगे। ऐसी बहुत सी परियोजनाओं में फिलहाल किसी भी समुदाय संगठन के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए नव संगठनों का जल्दबाजी में गठन किया गया।

अधिकतर उदाहरणों में ये ठोस नये समुदाय संगठन थोड़े क्षीण नजर आये क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य, परियोजना नियमों का अनुपालन करना था या यह सुनिश्चित करना था कि समुदाय सदस्यों का नकदी या श्रम की दृष्टि से ''लागत–सहभागिता'' में योगदान है या नहीं। क्योंकि इन समुदाय संगठनों को परियोजना के अंतिम चरण में सम्मिलित किया गया था और इन परियोजनाओं के सूत्रपात एवं कार्यान्वयन में वास्तविक समुदाय भागीदारी कोई खास नहीं थी, इसी कारण ये परियोजनाएं असफल हो गई और जब ये असफल हो गईं तो इसका पूरा दोष समुदाय आवासियों के मत्थे मढ़ना स्वाभाविक था।

ऐसी अधिकतर 'अद्योगामी' किस्म की परियोजनाओं में जिन सरकारी अधिकारियों और सहयोगी पेशेवरों की अहम् भूमिका होती है, उन्हें समुदायों को समझने या इन्हें अपने काम में शामिल करने में कोई रूचि नहीं होती और न ही ये लोग परियोजना रूपरेखा, नियोजन एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में रूचि रखते हैं। इन नव परियोजना–सृजित समुदाय संगठनों की भागीदारी, ऐसे पारंपरिक आवासीय वितरण कार्यक्रमों में सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक ही सीमित रहती है, जो कि बहुत पहले ही इनकी भागीदारी के बगैर ही तैयार कर लिए जाते हैं और इन कार्यक्रमों में लक्ष्य समूह की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं या वित्तीय क्षमताओं को सम्मिलित करने के लिए इनमें महत्वपूर्ण फेरबदल करने का कोई प्रावधान नहीं होता और यह इस बात को सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका है कि समुदाय संगठन कभी भी स्थायी रूप नहीं अपना पायेंगे।

वास्तविक समुदाय संगठन, जो गरीब व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य संघर्ष की राह का आधार हैं, की शुरूआत विभिन्न तरीकों से की जा सकती हैं। इनकी तत्काल शुरूआत की जा सकती है या ये निष्कासन के संघर्षों के फलस्वरूप उभर सकते हैं। यहाँ तक, कि ये एनजीओ अंतःक्षेप के माध्यम से या किसी बड़ी विकास परियोजना के भाग के रूप में शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन चाहे ये समुदाय संगठन अपने असल रूप में उभरे या नहीं या चाहे ये शक्तिरहित सांकेतिक संगठन ही बने रहें, अर्थात इनका स्वरूप जैसा भी हो, इसमें मुख्य बात यही है कि इनमें सम्मिलित जन भागीदारी कितनी सच्ची एवं शुद्ध है।

''बहुआयामी दृष्टिकोण रखना''

बहुत से समुदाय संगठन अब इस बात को समझ रहे हैं कि अपने आंदोलनों को जीवंत रखने का राज़, बहुत से मोर्चों पर एक साथ काम करने और साथ ही, बहुत सी गतिविधियों की शुरूआत करने में, छिपा हुआ है।

एक ही रात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इसमें वर्षों लग जाते हैं। इस सच को अधिकतर विकास अंतःक्षेपक एवं औपचारिक आवासीय कार्यक्रम मान्यता नहीं देते। शहरी गरीबी और आवासीय समस्याओं के हल खोजने के लिए समुदाय संगठनों में धैर्य एवं लक्ष्य पर बने रहना ज़रूरी है। कई गरीबों के लिए स्थिति में बदलाव लाना ज़रूरी होता है और ऐसी सामान्य इच्छाशक्ति की प्राप्ति, ऐसे यथार्थ साक्ष्यों के बिना नहीं हो सकती जो दर्शाएं कि बदलाव संभव है।

पिछले समय में, बहुत से उत्कृष्ट समुदाय संगठनों का गठन किया गया और ये सभी किसी एकल, महत्वपूर्ण समस्या (जैसे कि निष्कासन) के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया दर्शाने की दृष्टि से बेहद मज़बूत भी नज़र आए। लेकिन समाधान के बाद कमजोर हो गए। यदि समुदाय संगठन किसी एकल मुद्दे, एकल संकट पर अपनी एकजुटता प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किसी एक प्रायोगिक परियोजना पर ही निर्भर रहेंगे जो उस मुद्दे के निपटान या उस प्रायेगिक परियोजना की सफलता हेतु, बेहद दबाव और संघर्ष के दौरान यदि अपना हौसला खो दें तो संगठन बिखर जाएगा। स्वस्थ, सुदृढ़ समुदाय संगठन को फलने–फूलने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है और यह तब अच्छे से फलता–फूलता है जब भिन्न–भिन्न समस्याओं के निवारण के लिए भिन्न–भिन्न मोर्चों पर व्यस्त रहता है और यह कार्य वह एक ही समय में अलग–अलग तरीकों से पूरा करता है।

शीला पटेल, (स्पार्क) बहुत से मोर्चों पर कार्रवाई की ज़रूरत को ''बहुआयामी दृष्टिकोण रखना'' कहती हैं। उनका मानना है कि जब आप एक बर्तन के तैयार होने का इंतजार करते हैं तो दूसरा शायद इस अवस्था में है कि आग में काफी पक गया है और उसे भट्ठी से निकालना ज़रूरी है। उनका मानना है कि कुछ न कुछ सदैव ऐसा उपलब्ध होता है जिससे उत्सुकता एवं जोश कायम रहता है जबकि उस समय कुछ अन्य मुद्दे अछूते ही रहते हैं। इसका अभिप्राय किसी एक बात को पूरे निखार तक पूरा करने तथा तत्पश्चात् दूसरी को पूरा करने से भिन्न है। जब बड़े और छोटे बर्तन अलग–अलग भट्टियों में पकने के लिए रखे जाते हैं तो इतनी फुरसत अवश्य मिल जाती है कि सभी बर्तनों पर एक–साथ निगरानी की जा सके।

बहु आयामी दृष्टिकोण, किसी भी ऐसे गरीब समुदाय की व्यापक एवं विविध आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापित करना है, जहाँ महिला, पुरुष, बच्चों, युवा और संभवतया वृद्धों की भी, विभिन्न ज़रूरतें होती हैं और इनकी गरीबी के स्तर भी भिन्न–भिन्न होते हैं। यहाँ जितनी अधिक गतिविधियों की उत्पत्ति होगी, नए नेताओं की सृजना की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी और इससे ऐसे नए लोग भी नजर आएंगे जो जिन बातों को पूरा करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें उन में सम्मिलित करना संभव होता है। इससे समुदाय की शक्ति का प्रसार सक्रिय भागीदारी से अधिक लोगों तक होता है। जब ऐसे समुदाय ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के अवसर खोलते हैं तो विभिन्न गतिविधियाँ, गरीबी में उपस्थित तनावों एवं निराशाओं को समाप्त करने अवसर भी देती हैं।

स्रोत : एसीएचआर

चित्रः यूडीआरसी – मंगोलिया

समुदाय आंदोलन, जो निष्कासन के विरूद्ध संघर्ष से जन्में थे, उन्होंने स्वयं को अपने–अपने शहरों की आवासीय समस्याओं का हल खोजने की प्रक्रिया में सक्रिय नेताओं के रूप में रूपान्तरित कर लिया है

चित्र: एसीएचआर

विरोध से वार्ता और प्रतिरोध से सहयोग की ओर

अधिकतर एशियाई शहरी समुदाय आंदोलन, गरीबों से कानूनी तौर पर बस्ती खाली कराने के विरोध के चलते आक्रामक रूप से जन्म लेते हैं। जमीन से बेदखली की धमकी गरीब समूहों को अपनी बस्तियों की सुरक्षा के लिए एकजुट एवं संगठित बने रहने के लिए बाध्य करती है। ऐसे सामान्य संकट पर ध्यान केंद्रित करने से किसी और की भूमि पर गैरकानूनी कब्जाधारक के रूप में अपनी सांझी स्थिति पर गौर करने और अच्छे, सुरक्षित घर की सामान्य आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलती है। अपने घरों और रोजी–रोटी को बचाने के लिए, इन संघर्षों से गरीब समुदायों में बहुत से नए कार्यों की शुरूआत हुई है।

1 **इन संघर्षो से लोग शहरों को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं** कि ये लोग इन शहरों की वजह से ही सुविधाओं से वंचित हैं और कानूनी उत्पीड़न झेल रहे हैं तथा आवासीय अधिकारों से भी वंचित हैं।

2 **इन संघर्षो के फलस्वरूप समुदाय के सदस्य एवं संगठन ऐसे विस्तृत नेटवर्को से जुड़ते हैं** जिनके मन में संघर्षों के लिए काफी हमदर्दी है।

3 **ये प्रभावी निर्णयन संरचनाओं को विकसित करने** और गरीब समुदाय संगठनों में सक्षम एवं ज़िम्मेदार नेता को निर्मित करने में सहायक हैं।

4 **ये आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक निर्णयन** व्यवस्था एवं समुदाय सदस्यों में सहयोगपूर्ण भावना जागृत करने में सहायक होते हैं।

उपरोक्त प्रत्येक बिंदु का अभिप्राय अत्याधुनिक समुदाय संगठन का निर्माण करने से है जो अपनी बात रचनात्मक ढंग से पहुँचाने और उन प्राधिकारियों से समझौते की प्रभावी बातचीत करने संबंधी कौशलों से संपन्न हों, जो कभी इनके घरों को तोड़ने का आदेश देते थे।

संकट के प्रति अल्पकालिक, प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में इन मोर्चाबंद समुदायों के लिए जो शुरूआत हुई थी, वह धीरे–धीरे संवाद, समझौते आदि के मुद्दे की तैयारी के माध्यम से सुरक्षित आवासीय योजनाओं के दीर्घकालिक लक्ष्य पर केंद्रित होते हुए परिवर्तनकारी प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई।

यद्यपि आवासों से कानूनी निष्कासन निरंतर जारी रहा और गरीब लोगों को शहर से बाहर पटकने की कार्रवाई भी जारी रही, लेकिन कानूनी बेदखली को रोकने की लंबी लड़ाई से अंततः गरीबों के लिए धारणाधिकार और आवासीय समस्याओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ सामने आईं। ये उपलब्धियाँ, अन्य समुदायों एवं शहरों के लिए एक जैसे मुद्दों में होड़ लगाने में अहम् नज़र आने लगी और इससे, इन महत्वपूर्ण निर्णय संबंधी विकल्पों ने स्थानीय सरकारों और समुदायों को (एक–दूसरे के विरूद्ध आवाज उठाने की बजाय) एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि गरीबों और उस शहर के लिए लाभप्रद स्थायी आवासीय समाधानों की प्राप्ति हो, जिसका ये सभी हिस्सा हैं।

“हमारे पीछे खड़ें हों, न कि आगे – – हम अपने लिए खुद आवाज उठा सकते हैं।”

गैर सरकारी संगठन, जन संगठनों को विभिन्न तरीकों से सहयोग प्रदान कर इनके महत्वपूर्ण सहयोगियों की भूमिका निभा सकते हैं। गैर सरकारी संगठन औपचारिक व्यवस्था और वास्तविकता और गरीब जनजीवन के गठन की विवेकपूर्ण और उलझनपूर्ण राह की महत्वपूर्ण कड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन मज़बूत समुदाय संगठनों का अपने एनजीओ सहयोगियों के लिए संदेश है कि : *“हम अपने उत्थान के लिए स्वयं बात कर सकते हैं। हमारे आगे नहीं, बल्कि हमारे पीछे खड़े हों। यहाँ मुख्य बात जन प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है, न कि इन्हें मीठी बातों से झाँसा देना या इन्हें दूसरों पर निर्भर बनाना है।*

गैर सरकारी संगठनों ने बहुत से एशियाई देशों में गरीब समुदायों की सहायता करने में बड़ी भूमिका निभाई है ताकि ये संगठन खुद को स्व–संचालित संगठनों के रूप में संगठित करें और भूमि से आवासीय और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बनाने और स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी मुद्दों और बेहतर रोज़गार अवसरों जैसी अपने सम्मुख आने वाली समस्याओं का सामना पूरी क्षमता एवं शक्ति से कर सकें। वर्तमान समय में, कुछ ऐसे चुनिंदा देश हैं जहाँ स्वायत्त समुदाय संगठनों (और इनके एनजीओ सहयोगियों) को राष्ट्रीय स्थिरता के संबंध में चुनौती के रूप में देखा जाता है और कड़े नियंत्रण में रखा जाता है और इन एनजीओ –समुदाय गठबंधनों के फलस्वरूप शहरी आवासीय एवं गरीबी सम्बंधी समस्याओं के सबसे रोचक एवं अभूतपूर्व समाधान प्राप्त हुए हैं *(अधिक जानकारी के लिए इस गाईड के “भागीदारी” भाग को पढ़ें)।*

पिछले दो दशकों में, गैर सरकारी संगठनों को ऐसी नयी भागीदारी के मुख्य नायकों के रूप में तेजी से स्वीकारा गया है जिसने सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को गरीबी उन्मूलन, आवासीय एवं बुनियादी सेवाओं के मुद्दों, समुदाय संगठनों के संयुक्त प्रयासों एवं इनसे संवाद स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन इसके बावजूद गैर सरकारी संगठनों के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वे अपने समुदाय भागीदारों की तरफ से बातचीत करने या अपना वर्चस्व दिखाने की आदत से बचें परन्तु ऐसा करना सदैव आसान नहीं होता।

चित्रः यूएन हैबीटेट

जो निरंतर है:
परियोजनाएँ आती हैं और जाती हैं। गैर सरकारी संगठन, साथ छोड़ जाते हैं या अपना ध्यान बदल लेते हैं, दाता अनुदान शून्य नज़र आने लगते हैं, विकास प्रतिमान आते हैं और पुराने हो जाते हैं, पेशेवर बढ़ते रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं और बड़े सरकारी अफसरों के तबादले हो जाते हैं। विकास जगत में प्रवाह की कोटि अस्थिर लेकिन गतिशील है। जो निरंतर है वह है खुद गरीब समुदाय। करोड़ों खर्च किया और सलाहकार भी अपना काम करके चले गए, लेकिन गरीब लोग अभी भी सुरक्षित स्थान, रोज़गार की प्राप्ति, स्वच्छ शौचालय और पानी की बूँद के लिए यूँ ही भटक रहे हैं।

स्त्रोत : एसीएचआर

समुदाय भागीदारी: पूर्ण स्वामित्व से समझौते की ओर

हर तरीका मौजूद है जिससे समुदाय, भूमि, रोजी–रोटी कमाने और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने की समस्याओं के निपटान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वे सभी जो इन समस्याओं का प्रत्यक्ष सामना करते हैं, उन्हें इन समस्याओं की सबसे गूढ़ समझ होती है और इन लोगों में ही इन समस्याओं को हल खोजने की सर्वाधिक गूढ़ इच्छाशक्ति भी होती है। बावजूद इसके, बहुत से गैर सरकारी संगठन, विकास संगठन एवं सरकारी एजेंसियाँ, इनसे हर बात पर सलाह–मशवरा नहीं करती और परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ अपने विचारों को ही थोपने का प्रयास करती हैं। इसी तरह, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र सदैव भागीदारीपरक नहीं होता। यहाँ स्थानीय–निर्वाचित नेताओं द्वारा समुदायों से सलाह लेने की पर्याप्त गुंज़ाइश नहीं होती। दरअसल, समुदाय भागीदारी के बहुत से स्वरूप हो सकते हैं :

---

1 **पूर्ण स्वामित्व के माध्यम से भागीदारी :** समुदाय, निर्णयन प्रक्रिया से बँधे होते हैं और समुदाय के लिए जब आवश्यक होता है तब सरकार इनके कार्यों में दखल करती हैं। ऐसी भागीदारी में सरकार की मुख्य भूमिका नहीं होती बल्कि वह सिर्फ प्रतिक्रिया और सहयोग देती है और समुदाय अपने द्वारा पहचान की गई आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी पहलों को स्वयं नियंत्रित, कार्यान्वित और संचालित करते हैं।

---

2 **सहयोग के माध्यम से भागीदारी :** यहाँ, सरकार और समुदाय सांझे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर काम करते हुए, एक–दूसरे को सहयोग देते हैं और यह कार्य ठोस समुदाय निर्णयन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है और ऐसी प्रक्रिया को अक्सर गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुगम बनाया जाता है। समुदायों को प्रारंभिक चरण में शामिल किया जाता है और समुदाय के संवेदनशील समूह (अक्सर महिलाओं) को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

---

3 **परामर्श के माध्यम से भागीदारी :** समुदायों को अपने कामों में शामिल करने का काम अच्छी मंशा से किया जाता है और आमतौर पर यह मंचों का आयोजन करके किया जाता है। ये मंच लोगों को नियोजित अंतःक्षेप से अपने विचारों का आदान–प्रदान करने का अवसर देते हैं। यहाँ तक कि, यदि निर्णयन प्रक्रिया एवं सूचना को बाहरी एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो परियोजना को इन मंचों में अभिव्यक्त विचारों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। यद्यपि समुदायों का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता लेकिन इन्हें यदि अपनी बात कहने का मौका ही दे दिया जाए तो इससे परियोजना में कुछ हद तक जवाबदेही की भावना पनपती है।

---

4 **सूचना के माध्यम से भागीदारी :** इससे तात्पर्य है कि समुदाय हर काम में भाग ले रहा है लेकिन उन्हें तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि आगे क्या होगा और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वे इसे पसंद करेंगे या नही। लोगों के पास अपनी राय अभिव्यक्त करने या बदलाव को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती और यह प्रक्रिया आमतौर पर पारदर्शी नहीं होती। इस किस्म की 'भागीदारी' का उद्देश्य परियोजना को किसी भी संभावित विरोध से बचाना होता है (जैसे कि सड़क चौड़ीकरण के लिए समुदाय की भूमि को अपने कब्जे में ले लेना)।

---

5 **हेराफेरी के माध्यम से भागीदारी :** इस प्रकार की भागीदारी में समुदायों को सिर्फ शोषणात्मक कारणों से शामिल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की भागीदारीपरक निर्णयन प्रक्रिया विद्यमान नहीं होती और समुदायों का प्रयोग मुख्य रूप से राजनीतिक फायदों या निःशुल्क श्रम लाभ की प्राप्ति करने, लागत प्रतिपूर्ति या दाता संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

स्त्रोत : प्लूम्मर, 2000 द्वारा उद्धृत

भागीदारी: 7 तरीके जिनसे 'गरीब समुदाय संगठन', एशियाई शहरों में भूमि, आवासीय, बुनियादी सेवाएं एवं गरीबी संबंधी समस्याओं को हल करने में अपनी सरकारों की सहायता कर रहे हैं।

एशियाई क्षेत्रों में भूमि, आवास एवं बुनियादी सेवा संबंधी समस्याएं इतनी विशाल एवं जटिल हैं कि समुदायों, सरकारों, शहरों या विकास एजेंसियों के लिए अकेले इनका हल खोजना संभव नहीं है। ऐसी समस्याओं के समाधानों के लिए भागीदारी ज़रूरी है लेकिन यह भागीदारी इतनी आसान नहीं होती, विशेष रूप से गरीब और राज्य के बीच क्योंकि दोनों पक्षों का आपसी अविश्वास का लंबा इतिहास है।

किसी भी अच्छी भागीदारी का सिद्धांत है कि प्रत्येक पक्ष वही करे जिसे वह उत्कृष्ट ढंग से कर सकता है और अन्य कार्यों को वह पक्ष करें जो उत्कृष्ट ढंग से कर सकता है। इस तरह लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इस किस्म का समस्या–निपटान बहुपक्षीय है और इससे कुछ श्रेष्ठ समाधानों की प्राप्ति होती है। भागीदारी को विकसित करने में समय लगता है और यह सिर्फ निरंतर अभ्यास से ही किया जा सकता है।

ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें गरीब, राज्य की तुलना में बेहतर एवं अधिक सक्षम ढंग से कर सकते हैं। अनौपचारिक समुदाय पहले से ही ऐसी विशेषज्ञता या कौशल से संपन्न हैं जिनकी शहरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि मिस्त्री, बढ़ई, नलसाज, श्रमिक एवं बिजली ठीक करने वाले। जब ऐसे कार्यों में आत्मविश्वास बन जाता है तो कौशल और अधिक गूढ़ बन जाते हैं। नवीनता एवं संगठनात्मक क्षमताएं जिन्हें एशिया के समुदाय संगठनों ने विकसित किया है, पिछले दो दशकों में और अधिक बेहतर और उच्च स्तर की बन गई हैं और ये आपके प्रयोग हेतु वृहद् समस्या–निपटान संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं। यदि इन समुदाय संगठनों का कौशल, शहरों का निर्माण कर सकता हैं तो इन्हें काफी समय से उपेक्षित एशियाई शहरों की बड़ी आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी चैनलबद्ध किया जा सकता है।

सरकारी एजेंसियों एवं गरीब समुदायों के बीच की भागीदारी नये किस्म की है। जब सरकारी एजेंसियाँ पीछे हटकर वही करती हैं जो समुदाय एवं जनता नही कर सकती, तब प्रशासनिक अभिवृत्ति एवं दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त तालमेल बिठाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की भागीदारी और संबंधित नियंत्रण पद्धति, असल विकेंद्रीकरण की प्राप्ति हेतु सरकारों के लिए और गरीबों के जीवन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों में गरीबों की भागीदारी की रणनीति नज़र आती है। बहुत से एशियाई शहरों में गरीब समुदाय संगठनों को अब अपने–अपने शहरों में बड़े पैमाने की भागीदारी आधारित पहलों में और साथ ही अन्य प्रमुख व्यक्तियों को इन समस्याओं का प्रभावी एवं स्थायी समाधान खोजने के लिए शामिल किया जा रहा है। इन सांझेदारियों के परिणामों में वर्तमान विकास से जुड़े अधिकतर नवीन एवं रोचक कार्य सम्मिलित हैं। ये परियोजनाएं दर्शाती हैं कि शहर एवं गरीब समुदाय एक साथ काम कर सकते हैं और इससे हर एक का कल्याण होता है।

गरीबों की समस्याएँ पूरे शहर की समस्याएं हैं।

यह सिर्फ समता या अधिकारों का मुद्दा ही नहीं है बल्कि मूलभूत शहरी समीकरणों का मुद्दा है। शहर का हर एक भाग आपस में एक–दूसरे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि शहर का बुनियादी ढाँचा, शहर की आधी आबादी के जनित कूड़े–कचरे एवं अन्य गंदगी को नदी में बिना उपचार के ज्यों का त्यों बहाने की अनुमति देता है तो यह अल्प सुविधाप्राप्त गरीबों के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि पूरे शहर के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप गरीब महिलाओं के लिए जमीन, घर और बुनियादी सेवाओं की योजना बनाते हैं तो इससे समूचे शहर की भलाई होती है।

स्रोत : एसीएआर

भागीदारी व्यावहारिकता में:

1 आवासीय मामलों में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

उपाय

नोम पेन्ह (कम्बोडिया) शहर, इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार संगठित गरीब समुदाय, (यूपीडीएफ; स्थानीय समुदाय विकास निधि की सहायता से) अपने जिला, म्यूनिस्पिल एवं राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से शहर के गरीब नागरिकों को अच्छे एवं सुरक्षित घर प्रदान करने के अवसर सृजित कर सकते हैं – विशेष रूप से ऐसे संदर्भ में जहाँ एक समय निष्कासन ही आवासीय रणनीति थी। यहाँ जिस संदर्भ में भागीदारी उभरी है, उससे अधिक कठिन संदर्भ की कल्पना करना मुश्किल है। वर्षों चले युद्ध, राजनीतिक उथल–पुथल और बेहद तंगहाली ने न सिर्फ कम्बोडिया में समुदायों को पूरी तरह जीर्ण–शीर्ण कर डाला बल्कि इससे समुदाय, देश के अलग–अलग भागों में बिखर गए और उनकी पिछली पहचान भी विलुप्त हो गई। जैसे–जैसे देश स्थिर होने लगा और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगी तो जिलों आदि में बसे गरीब प्रवासी, शहरों में नई फैक्टरियों में रोज़गार की तलाश करने और व्यापारिक सेवाओं एवं पर्यटन क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे।

गरीबों के लिए नोम पेन्ह, उम्मीद और अवसर तलाशने का शहर है लेकिन जब बात अच्छी एवं सस्ती जमीन की हो तो प्रत्येक गरीब के पास शहर की 550 विषम अनौपचारिक बस्तियों, खुली जमीन और सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक, नहरों एवं नदियों के बेहद दूषित एवं अनुरक्षित वातावरण में डेरा जमाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शहर के विकसित होने के साथ–साथ शहरी भूमि पर बोझ बढ़ने लगा और गरीब समुदायों तथा आवासीय ठेकेदारों आदि के बीच मनमुटाव की भावना तेजी से पनपने लगी क्योंकि वाणिज्यिक हितों के चलते विस्तृत पैमाने पर गरीब बस्तियाँ खाली कराई गई थीं।

कम्बोडिया, अभी भी थाईलैण्ड एवं वियतनाम की तुलना में अपने गरीबों को औपचारिक सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। देश में अनौपचारिक बस्तियों

चित्र: एसीएचआर

के विनियमन के लिए कोई आवासीय बोर्ड नहीं है और न ही यहाँ आवासीय मंत्रालय का प्रावधान है और न ही कोई विधायी तंत्र है। यहाँ गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने या गरीब बस्तियों की दशा सुधारने के प्रयासों को सहयोग देने वाला कोई सरकारी कार्यक्रम भी विद्यमान नहीं है। यहाँ गरीब वर्ग हो या मध्य वर्ग अर्थात किसी के लिए भी आवासीय वित्त प्रदान करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यहाँ की नगरपालिका बाढ़ नियंत्रण, अपराध और आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों से पहले से ही दबी हुई है, और शहर की बढ़ती गरीब आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बेहद कठिनाई महसूस करती है।

वर्ष 1998 से शहरी गरीब बचत समूहों के नेटवर्क ने शहर के लगभग एक–तिहाई गरीब समुदायों के लिए आवासीय एवं बस्ती सुधार परियोजनाएँ विकसित करने के लिए अपने जिला एवं वार्ड अधिकारियों से विचार–विमर्श किया है। लचीले आवासीय ऋण एवं यूपीडीएफ से प्राप्त उचित अनुदानों से इन समुदायों ने 108 समुदायों में 3000 घरों के लिए योजना तैयार कर निर्माण किया और इस पर होने वाले खर्च को अदा किया – ये सभी कार्य शहर ही में हुए, जहाँ गरीबों के लिए कोई विकल्प नहीं था।

स्त्रोत : यूपीडीएफ/एसीएचआर

नोम पेन्ह कम्बोडिया में आवासीय भागीदारी

- **लोग अपने घरों एवं अपनी बस्तियों की रूपरेखा एवं निर्माण का कार्य खुद करते हैं।**
- **म्यूनिसिपैलिटी एवं प्रधानमंत्री नयी भूमि के लिए पैसा देते हैं।**
- **यूपीडीएफ आसान आवासीय ऋण एवं बुनियादी सहायता सेवाएं प्रदान करता हैं।**

15 वर्षों से गरीब परिवारों का एक समुदाय प्रेक तोयल की भूमि पर कब्जा करके रह रहा था। यह भूमि मीन शे (Mean Cheay) जिले में नोम पेन्ह के कूड़ाघर के बगल में है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग यहाँ से कूड़ा बीनते थे और कूड़े में पड़ी पुनःचक्रण योग्य वस्तुओं की बिक्री कर रोज़ाना एक–दो डालर कमा लेते थे। यहाँ की जीवन दशा बेहद खराब थी। यहाँ शौचालयों का अभाव था, सड़क या निकासी व्यवस्था मौजूद नहीं थी और चारों ओर गंदा पानी खड़ा था। जब वर्ष 2003 में समुदाय से जगह खाली करा ली गई तो नोम पेन्ह समुदाय नेटवर्क ने इस समुदाय को दैनिक बचत समूह शुरू करने में सहायता की और इनके लिए आसपास ऐसी भूमि तलाशनी शुरू की जिसे वे अंततः खरीद सकते थे। बचत नेटवर्क के माध्यम से म्यूनिसिपैलिटी को भी इस मामले का पता चला और उसने भी लोगों के स्व–सहायता आवासीय प्रयासों को सहयोग देने और पुर्नवास के लिए समुदाय की अपनी पसंद की भूमि खरीदने में सहायता करने पर अपनी स्वीकृति दे दी।

1 **भूमि :** लोगों ने मात्र 2 किमी. की दूरी पर 2 हेक्टेयर भूमि तलाश ली। पहले यहाँ फैक्टरी थी जो अब बंद थी। अतः लोगों को भूमि के साथ, फैक्टरी की पुरानी इमारत भी मिल गई जिसका प्रयोग समुदाय फिलहाल प्री–स्कूल और समुदाय केंद्र चलाने के लिए करता है। भूमि की कुल लागत 120,000 डालर थी जिसके लिए 40,000 डालर प्रधानमंत्री कोष और 80,000 डालर म्यूनिसिपैलिटी से प्राप्त हुए। सभी 159 परिवार (826 लोग) जुलाई 2003 में नई भूमि पर बस गए। इस जगह पर लगातार पाँच वर्ष रहने के बाद हर व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा।

चित्र: यूएन एसीफ

2 **बस्ती की रूपरेखा :** यूपीडीएफ के युवा वास्तुकारों की सहायता से यहाँ बसने वालों ने अपनी बस्ती का नक्शा तैयार किया, जिसमें खेल के मैदान, समुदाय केंद्र, कचरा रिसाइकलिंग वर्कशाप और प्रेक तोयल के कुल 159 परिवारों के लिए 72 वर्ग मीटर के 159 गृह प्लाटों की व्यवस्था थी।

3 **घर :** 59 परिवारों ने यूपीडीएफ से 200 से 500 डालर तक के आवासीय ऋणों की प्राप्ति की, जिन्हें वे अपनी अर्जन क्षमता के आधार पर मासिक, साप्ताहिक या दैनिक किश्तों में अदा करते हैं। अन्य लोगों ने रिसाइक्लड लकड़ी और अपने पुराने घरों की टीन की शीटों जैसी सामग्री के प्रयोग से अपने घरों का निर्माण किया और वे धीरे–धीरे इन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

4 **बुनियादी ढाँचा :** यूपीडीएफ और यूएन–हैबीटैट से प्राप्त पर्याप्त एवं अपग्रेडिंग अनुदान से निवासियों ने 866 मीटर सड़क, दो जल–निकासी लाइनों, सिलाई केंद्र और कुछ सांझे शौचालयों का भी निर्माण किया। म्यूनिसिपैलिटी ने सांझे नलों की व्यवस्था की। निवासियों का अगला कदम सड़कों को पक्का करना और पेड़ लगाना है।

स्त्रोत : www.achr.net

उदाहरण

2 पुनर्वास में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

मेट्रो मनिला में रेलवे लाइनों का अत्यावश्यक विस्तार इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पुनर्वास से गरीब किस प्रकार अधिक आहत नहीं होते जब समुदाय संगठन, विकास प्रक्रिया में मुख्य भागीदार हों।

जब वर्ष 1997 में सरकार ने परिवहन एवं कार्गो हेतु मनिला की रेलवे लाइनों के विस्तार एवं सुधार के लिए महा–परियोजना की शुरूआत की तो शहर ने इसका स्वागत किया था जो यातायात के ठप्प पड़ने एवं प्रदूषण की समस्या से बेहाल था। चूँकि परियोजना के लिए रेलवे ट्रैक के 15 मीटर के दायरे में भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए ट्रैक के साथ बसे 80,000 परिवारों की गरीब बस्ती को महसूस होने लगा कि उनसे अब यह जमीन कानूनी रूप से खाली करा ली जाएगी।

सर्वप्रथम, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को इस परियोजना के लिए फिलिपाईन्स सरकार को ऋण देना था लेकिन बाद में बैंक राजी नहीं हुआ क्योंकि साफ नज़र आ रहा था कि प्रभावित परिवारों को उचित ढंग से पुनर्स्थापित करने पर बेहद भारी खर्चा आएगा और फलस्वरूप परियोजना को लागू करना संभव नहीं होगा। एडीबी की असहमति के बाद, चीनी सरकार कंसोर्टियम (ठोस पुनर्वास दिशानिर्देशों के बिना) वित्तयन के साथ सामने आया।

परियोजना अपने उत्तरी एवं दक्षिणी घटकों से प्रभावित परिवारों के लिए ''शहर के भीतर'' पुनर्वास प्रदान करने पर लक्षित थी ताकि लोगों को बस्ती से कोसों दूर जाकर न बसना पड़े। चूँकि फिलिपाईन्स नेशनल रेलवे, प्रभावित लोगों को पुर्नवास देने वाली सार्वजनिक–निजी कंपनी है। इस काम के लिए परियोजना बजट में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि लोगों को पुनः बसाने का काम रेलवे का नहीं है। यद्यपि नेशनल हाऊसिंग अथार्टी पुनर्वास प्रक्रिया का काम बारीकी से देख रही है लेकिन प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी जहां से रेल गुजरती है (अपनी नीतियों एवं राजनीति सहित) अपनी–अपनी सीमा में पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है।

पुनर्वास पैकेज से लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :

- **सेवाओं से युक्त प्लाट :** (40 वर्ग मीटर), 2,200 अमेरिकी डालर की सस्ती कीमत पर जिसमें नये क्षेत्रों में पक्की सड़के, नालियाँ, बिजली और जलापूर्ति की लागत सम्मिलित है।
- **आवासीय सामग्री :** 870 डालर तक की और श्रम के लिए 220 डालर नकद
- **ऋण :** सेवा युक्त प्लॉट, निर्माण सामग्री और श्रम बजट अर्थात ये सभी सुविधाएं लोगों को लागत – वसूली के आधार पर मुहैया कराई जाएंगी। 3,290 डालर की कुल राशि 30 वर्षों में 6 प्रतिशत ब्याज के आधार पर मासिक किस्तों में अदा की जाएगी।

चित्र: पीएसीएसआई – फिलिपाईन्स

रेलवे स्लम्सः
लगभग 200,000 गरीब परिवार मनिला में रेलवे लाइनों के किनारे की अनौपचारिक बस्ती में बसे हैं। जहाँ ये रेल की आवा–जाही के आधार पर अपने जीवन को अनुकूल बनाते हुए हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। कोई भी ऐसी खतरनाक स्थिति में जीवन–यापन नहीं करेगा लेकिन अन्य आवासीय विकल्पों के अभाव में रेलवे ट्रैक की ये गन्दी बस्तियाँ वर्षों से ज्यों कि त्यों बसी हुई हैं।

चित्र: पीएसीएसआई – फिलिपाईन्स

"यदि हम किसी म्यूनिसिपैलिटी के सहयोग से किसी अच्छे पुनर्वास कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं तो हम ऐसे कार्यक्रम की सफलता का प्रयोग किसी अन्य म्यूनिसिपैलिटी को प्रभावित करने के लिए भी कर सकते हैं। जिसकी पुनर्वास के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह पुनर्वास के पथ प्रदर्शक संयुक्त प्रयास की भांति है। ऐसी कुछ म्यूनिसिपैलिटी में लोगों को काम की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन अब बोके (Bocaue) म्यूनिसिपैलिटी के लोग अन्य म्युनिसिपैलिटियों को रेलवे स्लम बस्तियों की ताजा जानकारी देने के लिए जाने लगे हैं। इस तरह प्रभावित परिवार, अन्य प्रभावित परिवारों की सहायता और सूचना का प्रसार करके एक नये नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं।"

रूबी पापेलेरस, एचपीएफपी

मनिला, फिलिपाईन्स में पुनर्वास भागीदारी

होमलेस पीपुल्स फेडरेशन फिलिपाईन्स (एचपीएफपी) शहरी गरीब समुदायों का राष्ट्रीय नेटवर्क है जो संवेदनशील स्लम बस्तियों को शहरी विकास प्रक्रिया में शामिल कर भूमि, आवास, बुनियादी सेवाओं एवं आजीविका अर्जन जैसे पहलुओं में समुदाय–चालित पहलों को बढ़ावा देता है। वर्षों से फेडरेशन, मनटिनलूपा के उत्तरी रेलवे ट्रैक के किनारे स्थापित बस्तियों में बचत समूहों को सहयोग प्रदान कर रहा है और वर्ष 2003 से उत्तर रेल परियोजना में जुटी छह नगर पालिकाओं में प्रभावित रेलवे बस्तियों के उत्थान के लिए जी–तोड़ मेहनत कर रहा है।

फेडरेशन के लिए, निष्कासन संकट और प्राकृतिक आपदाएं बेहतर एवं अधिक सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने की ज़िम्मेदारी उठाने के संबंध में गरीब समुदायों को एकजुट करने का प्रायः सशक्त अवसर हो सकती हैं। उत्तर रेलवे परियोजना के अंतर्गत हजारों घरों से बलात निष्कासन एक ऐसा अवसर था जिससे गरीबी को बढ़ाने वाले बलात् निष्कासन को समुदाय–नियंत्रित पुनर्वास प्रक्रिया में बदला जा सकता था जो जन उन्मुख एवं समुदाय–चालित विकास की विस्तृत एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया की ओर पहला कदम है।

तीन नगर पालिकाओं में रेलवे बस्तियाँ पहले से ही ठोस संयुक्त प्रयासों पर कायम थी और इसी गठबंधन ने सहायता हेतु होमलेस पीपुल्स फेडरेशन की ओर हाथ बढ़ाया। तीन नगर पालिकाओं में बचत योजना स्थापित करने और सभी प्रभावित बस्तियों में विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण करने के लिए रेलवे समुदायों की मदद करने के बाद फेडरेशन ने 'शहर के भीतर' नए स्थल का चयन करने और पुनर्वास के संबंध में समुदाय को स्थानीय सरकार से संवाद स्थापित करने में सहयोग दिया। फेडरेशन ने सभी नगर पालिकाओं में संसाधन केंद्रों की स्थापना की और आदान–प्रदान दौरों का आयोजन किया तथा बचत एवं पुनर्वास नियोजन में गरीब समुदायों द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए समुदाय नेताओं को निकटवर्ती पायटास (Payatas) में बुलाया गया।

स्रोत : www.achr.net

चित्र: एसीएचआर

उत्साह बनाए रखना :

बान मैनकांग के पैमाने पर अपग्रेडिंग कार्यक्रम को पूरा करना कुछ इसलिए संभव है क्योंकि अधिकतर थाई शहर पहले से ही वृहद, सक्रिय समुदाय नेटवर्कों से लैस हैं जो कि कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध अवसरों का तत्काल एवं उत्कृष्ट प्रयोग करने के लिए तत्पर हैं। कार्यक्रम पिछले दस वर्षों से इन नेटवर्कों के अथक प्रयासों की औपचारिक एवं निरंतर आगे बढ़ने की संकल्पना को दर्शाता है। बान मैनकांग इस ऊर्जा को संजोए रखने एवं परिष्कृत करने का अवसर देता है और गरीब समुदायों को विकास का निष्क्रिय लाभार्थी बने रहने की बजाय, बदलाव लाने वाले एजेंट का रूप प्रदान करता है।

3 अपग्रेडिंग में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

समुदाय और सरकार में भागीदारी का एक उत्कृष्ट एशियाई उदाहरण थाईलैण्ड बान मैनकांग अपग्रेडिंग कार्यक्रम है जो देश के वर्तमान स्लम समुदायों (और इनके नेटवर्कों) को 200 थाई शहरों में भूमि और आवास संबंधी समस्याओं के संबंध में स्थायी और व्यापक समाधान विकसित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक मुख्य स्थान देता है।

नेशनल हाऊसिंग अथार्टी के प्रथम समुदाय अपग्रेडिंग कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1977 में हुई और वर्तमान स्लम समुदायों की भू–पट्टेदारी की अवधि को बिना विचारे, सभी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का थाई सरकार का यह पहला प्रयास था। यह एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने इस विचार पर भारी स्वीकार्यता को दर्शाया कि लोगों को वही रहने दिया जायें जहाँ वे पहले से रह रहे थे क्योंकि जमीन से कानूनी निष्कासन की तुलना में यह लाभप्रद विकल्प के रूप में उभरा था, बशर्ते कि ऐसी बस्तियों में पर्याप्त सुधार संभव हो। लेकिन प्रारंभिक कार्यक्रम अधूरी लागत वसूली, अनुरक्षण और गुणवत्ता की समस्याओं के चलते समस्याग्रस्त हो गए। गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाला खर्चीला, अधोगामी दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत बिना सामुदायिक भागीदारी के अकेले सरकार ने ही हर कार्य को पूरा किया था।

वर्ष 2003 में थाई सरकार ने देश के शहरी गरीब नागरिकों की आवासीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वाकांक्षी नीति की घोषणा की। **दि बान मैनकांग अपग्रेडिंग कार्यक्रम** सरकारी निधियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता सेवाओं और सीधे गरीब समुदायों पर लक्षित आसान आवासीय ऋणों के रूप में चैनलबद्ध करता है। ये गरीब अपनी आवासीय, पर्यावरणीय एवं बुनियादी सेवाओं की योजना को स्वयं बनाते हैं और इस संबंध में उपलब्ध बजट का संचालन भी स्वयं करते हैं। प्रत्येक गरीब परिवार को स्वयं घर देने की बजाय, बान मैनकांग ने इस काम की ज़िम्मेदारी थाईलैण्ड स्लम समुदायों को सौंपी है।

सीओडीआई द्वारा लागू इस अपारंपरिक कार्यक्रम के भाग के रूप में, 200 शहरों की सभी बस्तियों के गरीब समुदाय सर्वेक्षण के लिए अपनी स्थानीय सरकारों, पेशेवरों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से काम कर रहे हैं और तत्पश्चात् अपग्रेडिंग प्रक्रिया की योजना बना रहे हैं जो पाँच वर्षों के भीतर संबंधित शहर में सभी बस्तियों को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। एक बार इन शहर व्यापी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो सीओडीआई, समुदायों के लिए सीधे केंद्र सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं आवासीय ऋण के लिए बजट आबंटन का मार्ग खोलेगा।

बैंकाक (थाईलैण्ड) में अपग्रेडिंग में भागीदारी

लगभग 23,800 गरीब परिवार बैंकाक की बैंग बुआ नहर के किनारे 12 स्लम बस्तियों में रहते हैं। रोज़ाना आग लगने, निष्कासन के खतरे से जूझते और निरंतर नहर को दूषित करने का दोष झेलते हुए, सदियों यहाँ जीवन–यापन करने के बाद बैंग बुआ नहर के किनारे बसे लोगों ने अपने समुदायों को बेहतर जिंदगी देने और अपनी भू–धारणाधिकार को सुरक्षित करने के लिए बान मैनकांग कार्यक्रम का लाभ उठाने का निर्णय लिया।

जिला अधिकारियों, निकटवर्ती विश्वविद्यालय और सी.ओ.डी.आई के सहयोग से 12 बैंग बुआ समुदायों ने नेटवर्क का गठन किया, बचत समूहों की शुरूआत की, सहकारी समिति का गठन किया और अपनी बस्तियों के पुनर्विकास तथा अपनी नहर को स्वच्छ रूप देने के लिए योजनाओं का निर्माण किया। ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप, समुदाय इस महत्वपूर्ण नहर को स्वच्छ बनाने में शहर के हितैषी संगठन बन गए हैं। नहर–किनारे बसे 200 समुदायों के बैंकाक शहर व्यापी नेटवर्क के सहयोग से बैंग बुआ, जिस सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा जमाए बैठे थे, अब वे उस संबंध में लंबी पट्टेदारी संबंधी करारनामें पर समझौते की बातचीत करने के योग्य थे। बैंग बुआ ने प्राधिकारियों को भरोसा दिलाया कि उसी जगह पर अपने समुदायों के पुनर्वास से न सिर्फ इस समुदाय बल्कि समूचे शहर का भी कल्याण होगा। काफी तोल–मोल करने के बाद बैंग बुआ समुदाय ने राजकोष विभाग की इस शर्त पर हामी भर दी कि यहाँ बसा प्रत्येक परिवार अपने घर के आकार के आधार पर एक–दो अमेरिकी डालर, मासिक भू–किराए के रूप में अदा करेगा। परिवार सहकारी समिति को किराया देते हैं जो तत्पश्चात् राजकोष विभाग को सामूहिक अदायगी करती है।

पहले तीन समुदायों का पुनर्निमाण दिसम्बर 2004 में शुरू हुआ और सभी 12 समुदायों को कुछ वर्षों में अपग्रेड कर दिया जाएगा।

12 समुदायों के नए घरों एवं बुनियादी ढाँचे के साथ नहर को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इसके किनारे नए पेड़ लगाए जा रहे हैं और 5 मीटर के एक खास लेन का निर्माण किया जा रहा है जिससे बस्तियों तक पहुँच आसान होगी, बच्चों को खेलने के लिए स्थान, लोगों की आवा–जाही और खोमचे वाले अपने खाद्य पदार्थों अन्य वस्तुओं को आसानी से बेच पायेंगे। बैंग बुआ समुदाय नहर–सफाई संबंधी पर्वों का नियमित आयोजन करते हैं और नहर के पानी को पुनः उपयोगी बनाए रखने के लिए जैव खाद और पानी के पौधों का प्रयोग करते हैं और नहर में जहरीले बहिःस्राव की मात्रा को कम करने के लिए ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार प्रदूषकों से निरंतर बातचीत करते हैं। समुदाय के हित में ''चल बाजार'' की भी योजना बनाई जा रही है।

स्त्रोत : सीओडीआई

चित्र: एसीएचआर

पूर्व *बैंग बुआ समुदाय की सुधार से पूर्व की स्थिति। कमजोर लकड़ी के घरों के कारण लोगों के मन में सदैव आग लगने का डर रहता था*

पश्चात *बैंग बुआ के नये घर यहाँ के लोगों की जरूरत एवं सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तीन तरह के डिज़ाइनों के अनुरूप निर्मित किए जा रहे हैं।*

चित्र: एसीएचआर

पगतमबेयांग ने बहुत सी परियोजनाओं के माध्यम से दर्शाया है कि जब शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों की पूर्ति होती है तो समूचे शहर का भी कल्याण होता है।

4 आवासीय वित्त में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

दक्षिणी फिलिपाइन्स में सेबु शहर स्लम पुनर्विकास तथा पुनर्स्थापना स्कीमों की मिसाल बनाने वाला शहर रहा है, जिसने गरीब समुदायों, नगर पालिका, निजी व्यावसायियों, भू–स्वामित्वों एवं गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से विविध प्रकार की प्रभावी भागीदारियों की शुरूआत की है। सेबु शहर इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि मुख्य नायक के रूप में किस प्रकार गरीब समुदायों की भागीदारियों से क्रमिक आधार पर शहरी आवासीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सेबु की अनौपचारिक बस्तियों को खाली कराने की नौबत अब न के बराबर है। निष्कासन के स्थान पर अब बहुत से नए व्यावहारिक विकल्पों पर नज़र टिकाई गई है और इनमें से भू–भागीदारी, भू प्रतिस्थापन, पुनः खरीद, स्वैच्छिक पुनर्वास और ऑन–साइट विकास जैसे विकल्प सम्मिलित हैं। मजबूत समुदाय, सुझाव लेने वाला नगरपालिका प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाओं का अपारम्परिक वैचारिक समूह तथा शहर व्यापी क्षमता को इकट्ठा करके भागीदारी बनाने में बरसों लग गए।

शहर के गरीब समुदायों के प्रति सेबु के नवीन दृष्टिकोण से जुड़ी एक रचनात्मक एवं ओजस्वी ताकत, पगतमबेयांग फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन ने पिछले 30 वर्षों से जमीन की प्राप्ति, आवासीय वित्त, सामाजिक आवास और किफायती बिल्डिंग मैटीरियल जैसे मुद्दों पर गरीब समुदायों, म्यूनिसिपैलिटी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। पगतमबेयांग ने समुदाय को ऋण देने या सामान गिरवी रखने संबंधी दर्जनों सामुदायिक गिरवी कार्यक्रमों को शुरू किया है। गैर सरकारी और समुदाय संगठनों के ठोस नेटवर्क से पगतमबेयांग ने अभियान चला कर कार्यक्रम के प्रशासनिक पहलू को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाने और अधिकाधिक परिवारों तक ऋण सुविधा को विस्तारित करने तथा सीएमपी कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्षों कड़ा संघर्ष किया है। *(आवासीय वित्त पर तत्काल गाईड 5 देखें)*

गरीबों का अपना वित्तीय कार्यक्रम

सेबु की बहुत सी आवासीय परियोजनाएँ सिर्फ सरकार के कम्यूनिटी मोर्टगेज कार्यक्रम की वजह से ही संभव हो पाई हैं। वर्ष 1993 और 1997 के बीच सीएमपी ने बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे (मूल व्यक्ति और समुदाय संघों के माध्यम से) 46,000 कब्जाधारी गरीब परिवारों को भूमि खरीदने और अपनी स्थिति को स्थिर बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिए। दुर्भाग्यवश ऋण की अदायगी न कर पाने जैसी समस्याओं ने इस नवीन कार्यक्रम को बीमार कर दिया। जो कि देश का एकमात्र ऐसा आवासीय कार्यक्रम था जिसका सरोकार सीधे शहरी गरीबों से था और जो बेहद निम्न बजट वाली समुदाय–संचालित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता था जो न तो ठेकेदारों और न ही विकासकर्ताओं को अपने काम का हिस्सा बनाती हों।

स्त्रोतः एसीएचआर

फिलिपाईन्स में आवासीय वित्त भागीदारी

1 **हालात :** इधर–उधर बसे 60 परिवारों का लघु समुदाय सेबु हॉस्पिटल के पीछे की बेहद उपयोगी वाणिज्यिक भूमि पर बसा था जिसे भूमि का मालिक अब खाली करवा कर विकसित कराना चाहता था। पगतमबेयांग ने हर प्रभावित व्यक्ति की सहमति के बाद 2 किमी. दूर स्थित सारिहे (Sareehay) के वृक्षों से घिरे बाहरी इलाके में वैकल्पिक भूमि की प्राप्ति करने में समुदाय की सहायता की।

2 **समझौता :** जिस जगह पर लोग वर्षों रहे थे, अब उसे खाली करने के बदले, जमीन के मालिक ने यहाँ से जाने और कहीं और बस जाने के लिए मुआवजे के रूप में (गृह आकार के आधार पर) काफी तोलमोल करने के बाद 1000 पेसोस (22 अमेरिकी डालर) प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्रत्येक परिवार से 'भूमि' खरीदने के प्रस्ताव पर हामी भर दी। इसके अलावा, जमीन के मालिक ने समुदाय की नयी भूमि को खरीदने और इसे पूर्णतया विकसित करने का भी बीड़ा उठाया और इस बात पर भी राजी हुआ कि ऐसी जमीन को पूर्णतया विकसित करने के बाद यह 'सारिहे सैनसियांगको रिवरसाइड होमओनर्स एसोसिएशन' के सुपुर्द कर दी जाएगी जो बाद में प्रत्येक परिवार को इसका मालिकाना हक सौंप देगी।

3 **परियोजना :** ईको–बिल्डर (पगतमबेयांग–निर्माण प्रभाग) से कान्ट्रेक्ट करने के बाद, भूमि के मालिक ने नई जमीन तलाशने और सारिहे में सड़क, जल निकासी और जलापूर्ति जैसे सुविधाओं की स्थापना के लिए, समुदाय स्थल योजना को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी भुगतान किया। यह योजना पगतंगबेयांग के विभिन्न सत्रों में मिल कर बनाई गई। योजना में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिवार पिछली बस्ती में ''किराएदार'' था या ''मकान मालिक'', अर्थात् इस आधार पर 36 और 54 वर्ग मीटर के प्लाट, समुदाय केंद्र और बीच में बड़े खेल के मैदान के लिए भी भूमि रखी गई।

4 **घर :** लोगों ने जमीन के मालिक से वसूली राशि से नए घर खरीदे। कुछ ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सीएमपी ऋण की प्राप्ति की। घर दो प्रकार के थेः ऊँची जगह पर सस्ते बाँस की झोपड़ियां और दुमंजिला मकान। अधिकतर परिवारों ने अपने घरों का निर्माण, अपने पुराने घर की पुनः प्रयोग योग्य सामग्री के प्रयोग से स्वयं किया। लेकिन कुछ ने यह काम ईको–बिल्डरों के सुपुर्द किया ताकि वे इनके लिए सस्ते, पंक्तिबद्ध घर बनायें जो कि माइक्रो–सीमेंट की छत और कम्प्रेस्ड अर्थ–ब्लॉक वाले हों और जहाँ कमरे की ऊँची छत हो ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया जा सके।

स्त्रोत : एसीएचआर

हर किसी की जीत

सारिहे ने सेबु में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाया जहाँ जमीन के मालिकों ने गरीब परिवारों से जमीन खाली करवा कर मुनाफा कमाया वहीं उन्हें नयी जमीन देकर पुनः बसने में सहायता करने का भी बीड़ा उठाया। इस प्रकार भूमि के मालिक ने जहाँ संपत्ति से मुनाफा कमाया वहीं निर्धन परिवारों को अच्छे एवं सुरक्षित घर भी प्रदान किए।

चित्र: एसीएचआर

उपरांत

5 स्वच्छता में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर संबधी बजट का अधिकांश, शहरों पर ही खर्च किया जाता है। लेकिन इन शहरों की स्लम बस्तियों की साफ–सफाई पर इस बजट का बहुत थोड़ा भाग ही खर्च किया जाता है। इसी वजह से शहरों में बसी आधी आबादी की स्वच्छ शौचालयों तक भी पहुँच नहीं है। लेकिन मुंबई एवं पुणे के कुछ सफल मामले इस बात का उदाहरण हैं कि जब सरकार ठान लें कि सार्वभौमक स्वच्छता प्राथमिकता का मुख्य मुद्दा है और प्रत्येक निर्धन परिवार को शहर में स्वच्छ शौचालय देने के लिए वह गरीब समुदाय संघ से हाथ मिला लें तो फिर कुछ भी असम्भव नहीं होता।

भारतीय शहरों के लाखों गरीब सड़कों के किनारे, रेलवे लाइनों एवं फुटपाथों पर मल का त्याग करते हैं और जिसके लिए उन्हें कड़ा अपमान और यातनाएं भी झेलनी पड़ जाती हैं। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं करेगा यदि उसके पास कोई अन्य विकल्प मौजूद हो, क्योंकि कई बार या तो शौचालय उपलब्ध नहीं होते या फिर इतनी खराब दशा या ऐसी जगहों में होते हैं कि खुली जगह पर मल त्यागना ही बेहतर मान लिया जाता है। भारतीय स्लम बस्तियों में बेहद खराब दशा और कम रोशनी वाले कुनियोजित शौचालय हैं जहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए यह दशा और अधिक शोचनीय नज़र आती है।

प्राधिकारी अब इस बात को मानने लगे हैं कि यदि शहर बुनियादी सेवाओं तक पहुँच के अभाव में अस्वच्छ एवं निम्न दशाओं में जीवन–यापन करते हैं तो पूरे शहर के रूप में यह बेहद शोचनीय स्थिति है। लेकिन अधिकतर सरकारी अधिकारी जो स्लम बस्तियों में साफ–सफाई के बारे में ज़रूरी निर्णय लेते हैं, वे स्वयं सुविकसित, समुदाय–संचालित शौचालयों की कल्पना नहीं कर पाते। ऐसी समझ के अभाव में बदलाव की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। ऐसे उदाहरण गिने–चुने हैं जिसमें किफायती किस्म के शौचालय बनाए जाएं जो दूसरों के लिए भी आदर्श सिद्ध हों।

वर्ष 1995 से, नेशनल स्लम–डवेलर्स फेडरेशन, महिला मिलन और स्पार्क के गठबन्धन ने समुदाय–संचालित शौचालयों के डिज़ाइन एवं निर्माण में 50 से अधिक भारतीय शहरों के स्लम समुदायों की सहायता की है। इस गठबंधन ने मुंबई, कानपुर और बंगलोर में 5 या 10 सीटों वाले शौचालय ब्लाकों की शुरूआत की। ये शुरूआती शौचालय इस विचार से तैयार किए गए थे कि हर कोई इन्हें देखें और इस व्यवहार को अपनाएं। इस गठबंधन ने गरीब समुदायों और सरकारों को भारत में ऊर्जा के सबसे बड़े स्त्रोत 'गरीब समुदाय' के प्रयोग से निर्मित बेहतर एवं सस्ते शौचालय प्रदान करने के, विभिन्न तरीकों से अवगत कराया।

चित्र: स्पार्क

सांझी लागत, सांझी ज़िम्मेदारी

राष्ट्रीय स्लम–डवेलर्स फेडरेशन का सरल लागत–सहभागिता शौचालय एक प्रतिमान है : समुदाय अपनी बस्तियों में प्रति चार परिवारों में एक शौचालय के अनुपात से सांझे शौचालयों की योजना, निर्माण एवं अनुरक्षण की शुरूआत करें। राज्य ऐसी जगह पर सीवर, जलापूर्ति एवं बिजली का प्रबंध करेगा और सामग्री संबंधी खर्च का भुगतान करेगा।

स्त्रोत : टायलेट टॉक, स्पार्क

चित्र: स्पार्क

एनएसडीएफ कम्यूनिटी टॉयलेट के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि स्लम के सांझे शौचालय कभी भी अस्वच्छ नहीं नज़र आने चाहिए। इनके बहुत से शौचालय इतने साफ–सुथरे हैं कि ये मिल वर्करों, हैड–लोडरों और रिक्शा चलाने वालों के लिए राहत–स्थल बन गए हैं और ये सभी स्वच्छ शौचालयों के प्रयोग हेतु एक रुपया अदा करने को तैयार हैं। ऐसे शौचालयों के बाहर अब लोगों का जमावड़ा नज़र आता है जहाँ चाय और खोमचेवालों ने अपना गढ़ बना लिया है।

मुम्बई, (भारत) में स्वच्छता में भागीदारी

एनएसडीएफ/महिला मिलन/स्पार्क गठबंधन ने अपने शौचालय निर्माण कार्यक्रमों में भारी बढ़ोतरी की है। जब इस गठबंधन को म्यूनिसिपल कमीशनर की पहल पर पुणे में 113 शौचालय ब्लाक (2000 सीटों) और विश्व बैंक (वित्तीय सहायता समर्थित) मुंबई स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत मुंबई में अन्य 320 शौचालय ब्लॉक (6400 सीटों) के निर्माण का ठेका मिला। दो परियोजनाएं जो 10 लाख लोगों को स्वच्छता प्रदान करती हैं, अब पूर्ण हो चुकी हैं और फिलहाल ये पूरी लगन से बहुत से अन्य शहरों में और अधिक शौचालयों के निर्माण में व्यस्त हैं। इस गठबंधन के समक्ष इन 433 शौचालय ब्लॉकों के निर्माण का प्रयोग करके गरीब समुदायों में शौचालयों के डिज़ाइन, निर्माण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण के लिए नए मानदंड एवं मानक स्थापित करने की चुनौती थी।

ऐसी क्या नवीन बात है जो इन शौचालयों में झलकती है?

- **बुनियादी सेवाओं का वितरण :** शौचालय निर्माण के अनुबन्ध संबंधी कार्यनीति ने रोज़गार सृजित किए, समुदाय कौशलों का निर्माण किया और नगरपालिकाओं एवं गरीब समुदायों के आपसी रिश्ते को संविदागत गतिविधि की बजाय सेवा वितरण का संयुक्त प्रयास बनाया।
- **डिज़ाइन संबंधी मानदंड :** पुराने नगरपालिका ब्लाकों में स्त्री एवं पुरुष शौचालय अलग–अलग नहीं थे और यहाँ जलापूर्ति भी नहीं थी। नए शौचालय इस प्रकार के हैं कि इनके भीतर विविध प्रकार की सुविधाएं हैं। इनमें अलग स्त्री और पुरुष शौचालय, अलग बाल शौचालय, अलग मूत्रालय, निजी स्नानगृह, जलापूर्ति एवं भंडारण सुविधाएं, प्रतीक्षाकक्ष, देखरेख करने वाले का कमरा और कई जगह चाय और पान की दुकानें हैं।
- **ठेका लेना :** बहुत से समुदायों में महिलाओं ने समुदाय से कामगारों को दैनिक मजदूरी पर लेकर धन प्रबंधन, निर्माण कार्य की देखरेख और इंजीनियरों एवं म्यूनिसिपल इंस्पेक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करके शौचालयों के ठेकों का पूरा काम लिया है।
- **भागीदारी :** परियोजना ने म्यूनिसिपैलिटियों और समुदायों के बीच की भागीदारी की प्रकृति को बदल दिया और उस दृष्टिकोण को भी बदल डाला जिससे शहर, सेवा–वितरण ठेकों को पूरा करने के लिए समुदायों और गैर–सरकारी संगठनों से संवाद स्थापित करना होता था।
- **वित्त :** दोनों शहरों में शौचालयों के निर्माण और समुदाय–अनुरक्षण, जलापूर्ति और बिजली के लिए शहर ही भुगतान करता है।
- **अनुरक्षण :** शौचालयों का रखरखाव समुदायों द्वारा या फिर शहर–व्यापी महिला मिलन सांझेदारी या स्थानीय समुदायों द्वारा स्वयं किया जाता है। ये प्रति परिवार 10 रुपए वसूलते हैं। सभी शौचालयों में नियंत्रक कक्ष की सुविधा है।

स्त्रोत : एसीएचआर

6 इन्फ्रास्ट्रक्चर में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

- समुदाय डिजाइनर के रूप में
- समुदाय इंजीनियर के रूप में
- समुदाय ठेकेदार के रूप में

श्रीलंका समुदाय ठेका प्रणाली इस बात का अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार सरकार समुदायों को हर काम की ठेकेदारी सौंप कर इन्हें ही डिज़ाइनर, बिल्डर एवं प्रबंधक का दर्ज़ा देते हुए अपेक्षाकृत निम्न बजट या साधारण प्रयासों के माध्यम से किस प्रकार शहर के गरीब समुदायों को दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के वितरण को सुगम बना सकती है।

कोलंबो की लगभग आधी आबादी इसकी 1506 गरीब बस्तियों में रहती है। ये बस्तियाँ 60 से 1200 परिवारों के आधार पर अलग–अलग आकार की हैं। इनमें से कुछ की दशा बेहद खराब है। वर्ष 1980 से समुदाय ठेका पद्धति के अंतर्गत अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारों की योजना बनाने एवं लागू करने के लिए, बहुत से समुदायों को सहयोग दिया गया है।

सामुदायिक ठेकों संबंधी विचार की उत्पत्ति सर्वप्रथम राष्ट्रीय सरकार के नवीन, समुदाय–आधारित मिलियन हाउसिस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 1985 में 51 श्रीलंकाई कस्बों एवं शहरों में, नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट अथार्टी द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहयोग से हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक समुदाय ने समुदाय विकास परिषदों का गठन किया जो वर्तमान बस्ती का सर्वेक्षण एवं नक्शा तैयार करेंगी और एनएचडीए के सहयोग से प्रत्येक समुदाय के लिए घरों, गलियों, समुदाय स्थलों एवं अवसंरचनीय नेटवर्कों के संबंध में नए खाकों की योजना तैयार करेंगे।

चित्र: यूएन हैबीटेट

मिलियन हाउसिस प्रोग्राम के अंतर्गत, समुदाय अपने एवं प्राधिकारियों के बीच समुदाय ठेको के माध्यम से अपने द्वारा नियोजित एवं निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए लघु सरकारी अनुदानों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ठेकेदारों और इंजीनियरों को नियुक्त करने की बजाय समुदाय ने जलापूर्ति सिस्टम, शौचालय, जल–निकासी, फुटपाथ और उचित सड़कों आदि जैसे कार्यों का निर्माण किया और इस काम में सरकार ने समुदायों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से अपना समर्थन दिया। समुदायिक ठेका पद्धति से समुदाय का इन्फ्रास्ट्रक्चर वितरण पर पूर्ण नियंत्रण कायम हो गया और अपने लक्ष्य की पूर्ति में, यह बेहद सरल, लचीली, पारदर्शी एवं समुदाय–निर्मित रणनीति के रूप में उभरी।

वर्ष 1984 से 1989 के बीच कोलंबो के 38,000 से अधिक परिवारों ने अकेले ही कार्यक्रम के अंतर्गत अपने आवासीय एवं जीवन–यापन परिवेश में महत्वपूर्ण सुधार कर लिये और इसका सीधा असर इन परिवारों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक खुशहाली पर पड़ा। मिलियन हाउसिस प्रोग्राम की वर्ष 1993 में यकायक समाप्ति हो गई लेकिन समुदायिक ठेका पद्धति श्रीलंका में अभी भी छोटे पैमाने पर जीवंत है और अभी भी सरकार स्थानीय प्राधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के सहयोग से समुदायों को अपनी बस्ती के बुनियादी ढाँचे की रूपरेखा बनाने, लागू करने और संचालन एवं रखरखाव करने के लिए, सशक्त कर रही है।

स्त्रोत : सेवान्था

चित्र: एसीएचआर

जब निर्धन समुदाय सभी काम स्वयं निपटाते हैं तो यह किफायती सिद्ध होता है :

सरकार को पूरवारामा के 109 परिवारों को जलापूर्ति, जल–निकासी एवं सीवर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने में सिर्फ 29,000 अमेरिकी डालर की कुल लागत का वहन करना पड़ा। इससे आशय है कि प्रति परिवार मात्र 266 डालर, जो कि सरकार या निजी ठेकेदार द्वारा उसी कार्य को करने का एक अंश मात्र है।

स्त्रोत : सेवान्था

श्रीलंका में इन्फ्रास्ट्रक्चर भागीदारी

पूरवारामा समुदाय (कोलंबो) का उत्थान, सरकार–समुदाय सांझेदारी का बेहद उत्कृष्ट उदाहरण है जो समुदाय ठेका पद्धति को बढ़ावा देती है ताकि निर्धन समुदायों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। वर्ष 1999 में 109 परिवारों को पूरवारामा में फिर से बसाया गया। इससे पहले वे अपनी 50 वर्ष पुरानी बस्ती में बसे हुए थे जिसे खाली न करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष भी किया था क्योंकि हस्पताल प्रोजेक्ट के लिए मार्ग चाहिए था। निर्धन परिवार अंततः पुनर्वास पैकेज पर समझौते की बातचीत करने में सफल हो गए और उन्हें नजदीकी भूमि पर 50 वर्ग मीटर के प्लॉटों की निःशुल्क प्राप्ति हुई। इस नयी भूमि की खोज, लोगों ने स्वयं ही की थी। इन लोगों को मुआवजे में कुछ नकदी भी प्राप्त हुई थी ताकि वे अपने अस्थायी घरों का निर्माण कर सकें। लेकिन यहाँ बुनियादी सेवाओं का अभाव था। गैर सरकारी संगठन–सेवान्था की सहायता से इन लोगों ने अपनी ज़रूरतों की पहचान की और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत किया और बस्ती सुधार योजना विकसित की। पूरवारामा समुदाय विकास परिषद ने तत्पश्चात् सुधार संबंधी कार्यों को अलग–अलग परियोजनाओं में वर्गीकृत कर दिया ताकि वित्तीय सहायता की प्राप्ति के लिए इन सभी परियोजनाओं को विशिष्ट सामुदायिक ठेका प्रस्तावों के रूप में शहरी बस्ती सुधार परियोजना या सड़क विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

1. **प्रत्येक परिवार हेतु नल की व्यवस्था :** प्रथम समुदाय अनुबन्ध कार्यक्रम में सभी 109 घरों को वैयक्तिक आधार पर मीटर चालित वाटर कनैक्शन देने का मुद्दा सम्मिलित था, जिसके लिए सड़क विकास प्राधिकरण ने अनुदान के रूप में 6,000 डालर की वित्तीय सहायता दी। इसी कार्यक्रम में समुदाय ने भी प्रति परिवार 36 अमेरिकी डालर का योगदान दिया था। समूचा निर्माण कार्य, स्थानीय निवासियों ने अपने श्रम से स्वयं पूरा किया था।

2. **अपशिष्ट जल निकासी :** दूसरे अनुबन्ध में समूचे समुदाय से अपशिष्ट जल निकासी की नालियों को बना कर प्रत्येक घर की रसोई और स्नानागृह से जोड़ना शामिल था और इसके लिए शहरी बस्ती सुधार परियोजना (यू एस आई पी) ने अनुदान के रूप में 9,500 अमेरिकी डालर तथा प्रति परिवार 5 अमेरिकी डालर का योगदान दिया गया। समुदाय के श्रमिकों की सहायता से समूचा निर्माण कार्य स्थानीय वासियों ने स्वयं ही पूरा किया।

3. **सीवर नेटवर्क :** अगले अनुबन्ध में सभी 109 परिवारों के शौचालयों के लिए भूमिगत सीवर सिस्टम को लागू करना था। राष्ट्रीय आवासीय विकास प्राधिकरण ने 13,500 डालर का अनुदान दिया और साथ ही, समुदाय ने भी प्रति परिवार 5 डालर का योगदान दिया। समुदाय ने अपने और सेवान्था की तकनीकी सहायता से समूचे सिस्टम के डिज़ाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य स्वयं पूरा किया तथा अपने–अपने शौचालय के निर्माण की ज़िम्मेदारी भी उठाई।

7 आपदा पुनर्वास में समुदाय संगठनों के साथ भागीदारी

सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकांश राहत कार्य जो कि आपदाओं के होने के बाद किया जाता है, कल्याण के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत लोगों को निःसहाय पीड़ितों के रूप में देखा जाता है। निस्संदेह, बड़ी आपदा के घटित होने के बाद मदद की कड़ी जरूरत होती है। लेकिन थाईलैण्ड में सुनामी (2004) कहर का अनुभव दर्शाता है कि जब प्रभावित समुदायों को सरकार और राहत एजेंसियों की भागीदारी में निजी राहत और पुनर्वास की ज़िम्मेदारी उठाने में सहयोग दिया जाता है तो हर कोई इसमें शामिल होता है और ऐसी प्रक्रिया से समुदाय को मज़बूती मिलती है।

सुनामी के दक्षिणी थाईलैण्ड में कहर बरपाने के बाद समुदाय संगठन विकास संस्थान (सी ओ डी आई) ने देश के दक्षिणी भाग में परिचालित गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों, समुदाय नेटवर्कों और सरकारी संगठनों से यह समझने के लिए बातचीत की कि किस प्रकार ये सभी एकजुट हो कर सर्वाधिक प्रभावित छः प्रांतों के सुनामी पीड़ितों की सहायता कर सकते हैं।

यह स्पष्ट था कि ऐसे बड़े पैमाने के कहर के बाद तत्काल एवं प्रभावी राहत पहुँचाने का काम किसी सरकार या एकल संगठन के बस की बात नहीं है। इसलिए अब आवश्यकता थी संयुक्त–सहयोग, कौशल एवं विविध समूहों के सामूहिक संसाधनों, एकल प्रयासों और राहत एजेंसियों एवं समुदाय नेटवर्कों की अर्थात सभी को एकजुट कर राहत कार्यों को लागू करना। दि सेव दि अंडमान कम्यूनिटिज़ नेटवर्क की तत्काल स्थापना की गई और क्षति का पता लगाने और टेंट, कपड़े, दवाई, भोजन, पानी, ताबूत आदि के रूप में सुनामी – प्रभावित ग्रामों में राहत सहायता की शुरूआत की गई और मृत व्यक्तियों की खोज करने के लिए तुरंत कार्यकारी दलों को प्रत्येक प्रभावित प्रांत की ओर रवाना किया गया। एक ही सप्ताह में राहत शिविरों में अस्थायी आवासीय सुविधा के निर्माण की शुरूआत हो गई।

सुनामी से उत्पन्न मौत एवं नुकसान का तांडव देखने के बाद, जब हकीकत सामने आई तो गरीबी, सामाजिक बहिष्कार एवं भू–पट्टेदारी की बहुत सी गूढ एवं पूर्व–विद्यमान समस्याएं उभर कर साफ नज़र आने लगी। सुनामी से कुछ नई किस्म की समस्याओं का भी जन्म हुआ जब लोगों की रोज़ी–रोटी, सामाजिक संरचनाएं, उत्तरजीविता और उनकी जीवन–शैली तथा नावों सहित उनके घर ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन ऐसी विनाशकारी स्थिति के साथ, पहले से बेहद संवेदनशील तटीय समुदायों के लिए राह प्रक्रिया का प्रयोग करके इन गूढ और भविष्य को जोखिम में डालने वाली बेहद संरचनागत समस्याओं से निपटने का एक अप्रत्याशित अवसर भी प्राप्त हुआ।

स्त्रोत : www.achr.net

सीओडीआई और इसके भागीदारों ने सुनामी द्वारा प्रभावित तटीय समुदायों को संगठित एवं सुदृढ़ करने और पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य स्थान देने तथा इनकी बात को इनके शब्दों में व्यक्त करने के लिए राहत प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू के प्रयोग का निर्णय लिया और तय किया कि मात्र कमज़ोर और पीड़ित बने रहने के बजाय, असल में इन्हें क्या कदम उठाने चाहिए।

चित्र: बैंकाक पोस्ट

सुनामी – प्रभावित थाईलैण्ड में आपदा प्रबंधन में भागीदारी

बैंग मुआंग शिविर में जन–संचालित राहत

सुनामी कहर के तुरंत बाद साफ हो गया था कि सबसे ज़रूरी बात लोगों को अस्थायी आवास प्रदान करना है ताकि सुनामी से बिखरे लोगों को एकजुट किया जा सकें। जिससे वे स्वयं को संगठित, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण और अपने भविष्य की सांझी छवि विकसित करने की शुरूआत कर सकें।

अंडमान तट के आसपास सहायता संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों के प्रयास से तुरंत शिविर लगाये जा रहे थे। फंगन्गा (Phangnga) (सर्वाधिक प्रभावी प्रांत) में सीओडीआई नेटवर्क ने बैंग मुआंग में पहले एवं सबसे बड़े शिविर की शुरूआत करते हुए, पाँच शिविरों को तैयार करने में सहायता की। यद्यपि 400 की योजना थी लेकिन शिविर से अंततः 3500 लोगों को आश्रय की प्राप्ति हुई और ये सभी व्यक्ति थाईलैण्ड के सर्वाधिक प्रभावित निकटवर्ती ग्राम बैन नेम खेम के थे जहाँ 2000 से अधिक लोग मौत के शिकार और 1300 घर तबाह हो गए थे।

बैंग मुआंग शिविर की अनूठी बात यह थी कि इस शिविर की देखरेख स्वयं सुनामी पीड़ितों ने की थी। समुदाय नेटवर्क प्रमुख, सीओडीआई और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों ने जीवित बचे व्यक्तियों के साथ मिल कर शिविरों का निर्माण किया। शौचालय, स्नानगृह, रसोई एवं राहत–गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के बाद, प्रबंधकों ने अपने–अपने लीडर सहित 10 परिवार समूह और 3 समूह जोन के आधार पर साफ–सुथरे टैंटों को पंक्तिबद्ध रूप से तैयार किया। भोजन पकाने, शिविर–स्वच्छता, जलापूर्ति, चिकित्सा देखभाल, मिलने आने वाले बाहरी व्यक्ति, बच्चों के कार्यकलाप, गुमशुदा व्यक्ति, नए पीड़ितों का पंजीकरण, अनुदान और अस्थायी गृह निर्माण आदि के लिए समितियों का गठन किया गया। हर रात को शिविर व्यापी सभाओं का आयोजन किया जाता था ताकि शिविर प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं पर तथा अन्य ज़रूरी घोषणाएं की जा सकें और समितियाँ अपने दैनिक कार्य की रिपोर्ट दे सकें। हर कोई इस बात से भलीभांति परिचित था और प्रत्येक निर्णय, सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में सर्वसम्मिति से लिया जाता था। नौका मरम्मत की वर्कशाप, बचत समूह और कम्यूनिटी बैंक की शुरूआत की गई और जिन लोगों की रोज़ी–रोटी ठप्प पड़ गई थी, ऐसे पीड़ितों को संकट से उबारने के लिए आजीविका अर्जन कार्यक्रमों की शुरूआत की गई और सरकारी मुआवजे देने की भी मंद गति से शुरूआत की गई।

हर तरफ मातम छाया था लेकिन जहाँ सहानुभूति दर्शाने वाले बाहरी व्यक्तियों के आँखों में आँसू थे, वहीं उन सभी ने पीड़ितों की आँखों में आत्मविश्वास की चमक देखी जिससे वह जगह शरणार्थी शिविर की बजाय गाँव के मेले की अनुभूति दे रही थी। यहाँ जीवन थमा नहीं अपितु निरंतर गतिशील था।

www.achr.net

आपदा, विकास के अवसर के रूप में :

मुख्य विचार सुनामी कहर में जीवित बचे लोगों के लिए ऐसे व्यावहारिक तरीकों का पता लगाना था ताकि ये अपने शिविर को जीवंत बनाए रखने में सहयोग दे और यहाँ तक कि ऐसी बेहद गंभीर स्थिति में भी अपने जीवन के यथासंभव पहलुओं की देखरेख पूरी सक्रियता से कर सकें। और अपनी देखरेख स्वयं करते हुए, ये अपनी पूर्व–स्थिति की पुनः प्राप्ति कर सकें।

चित्रः एसीएचआर

उपागम

चित्र: होमलेस इन्टरनेशनल

अधिकांश अच्छे साधन लोगों को एकजुट और शिक्षित करते हैं। ये दुधारी होते हैं : भू–पट्टेदारी, सुरक्षित घर, बुनियादी सेवाएं और रोज़गार जैसे मुद्दों पर अपने संघर्ष में, इनका समुदायों के लिए व्यावहारिक और रणनीतिक मूल्य होता है।

6 साधन जिनका प्रयोग समुदाय अपने संगठनों के निर्माण के लिए करते हैं

जब हम एशियाई देशों में विद्यमान बहुत से समुदाय संगठनों पर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं :

1. क्या इन समुदाय संगठनों और इनकी सरकारों के बीच कोई समझौते की बात चल रही है?
2. यदि हाँ, तो इन समझौतों को पूरा करने में कौन से कौशल इन समुदायों के लिए सहायक हैं और इन कौशलों के निर्माण में कौन से साधन सहायक हैं?

अपने शहरों में समुदायों के सम्मुख आने वाली समस्याओं से जूझने में लाभप्रद विकास भागीदारों के रूप में प्रस्तुत करने से पहले समुदायों को स्वयं तैयारी करनी होगी। इस तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग समुदाय के भीतर मजबूत, लोकतांत्रिक निर्णयन तंत्र का निर्माण करना है जिससे समुदाय के सभी सदस्यों अर्थात अमीर–गरीब, मकान मालिक और किराएदार के हितों का प्रदर्शन होता हो। अन्य भाग, सामूहिक रूप से धन की देखरेख, नेटवर्कों से जुड़ना, वैकल्पिक जमीन की प्राप्ति, और जन–उत्तरजीविता तथा शहर विकास के मुद्दों पर केंद्रित यथार्थवादी वैकल्पिक आवासीय योजनाओं के लिए कौशल विकसित करना है।

समुदाय लीडरों को ''महत्वपूर्ण जनसमूह'' गठित करने के लिए न सिर्फ अपने समुदाय बल्कि अन्य निर्धन समुदायों को एकजुट करने के लिए ऐसे साधनों की ज़रूरत होती है जो कि विस्तृत पैमाने पर असल बदलाव लाने की पहली शर्त है। ये ऐसे साधन हैं जो एशिया के समुदाय आंदोलनों के अनुभवों एवं व्यावहारिक कार्यों के फलस्वरूप धीरे–धीरे उभर रहे हैं और जिनका सक्रिय प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है।

जब गरीब समुदाय कोई कार्य करते हैं और उसे लाभप्रद पाया जाता है तो इसे निरंतर दोहराया जाता है। बार–बार करने से यह समुदाय की विशेषता बन जाता है और इसका प्रयोग गहराई से किया जाता है। जितना अधिक इसका प्रयोग होता है, यह उतना ही उत्कृष्ट और मानक रूप धारण कर लेता है। इससे पहले कि आप इस बात को समझें, आप एक अच्छे साधन से संपन्न हो चुके होते हैं। ये साधन निरंतर बदलाव एवं अनुकूलता से अन्य जगहों पर नए रूप में उभरते हैं और इससे नए साधनों की सृजना होती है। ऐसे सभी साधनों के प्रयोग से मनुष्य धीरे–धीरे इनके प्रयोग में दक्षता हासिल कर लेता है और आगे चलकर सरकार से इस संबंध में मोल–तोल करता है। ऐसे ही कुछ साधन हैं जो घर डिज़ाइन करने की संभावनाओं की छानबीन करने, बचत समूह गठित करने या अपनी–अपनी बस्तियों के हालात का विश्लेषण करने में समुदायों के लिए सहायक हैं।

स्त्रोत : फेस टू फेस, www.achr.net

साधन 1 : बस्ती की परिगणना

गरीब व्यक्तियों द्वारा स्वयं बस्ती की गणना करना एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकता है। जब गरीब लोग ऐसी जानकारी एकत्र करते हैं तो यह समुदाय को एकजुट करने का महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। जब समुदाय एवं इनके नेटवर्क, शहर की सभी गरीब एवं अनौपचारिक बस्तियों का सर्वेक्षण करते हैं तो अक्सर ऐसे आँकड़े एकत्र होते हैं जिन्हें पहले कभी भी संख्या, रोज़ी–रोटी, शहरी आबादी के बड़े भाग की समस्याएं एवं जीवन–यापन संबंधी समस्याओं की दृष्टि से एकत्र नहीं किया गया।

गणना, गरीब समुदायों को यह अनुभूति देती है कि वे अकेले नहीं हैं और इनके सम्मुख आने वाली समस्याएं वृहद् संरचनागत मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। जो जानकारी लोग एकत्र करते हैं, अक्सर सरकारी आंकड़ों की तुलना में अधिक सटीक और विस्तृत होती है, इसलिए इससे स्थानीय क्षेत्र की योजना बेहतर और उपयुक्त ढंग से बनाना संभव होता है और जब भूमि या अधिकार तक पहुँच स्थापित करने के लिए तोल–मोल करने की बात आती है तो यह गरीबों के लिए शक्तिशाली साधन प्रतीत हो सकती है। सर्वेक्षण आधारित अच्छी जानकारी से लैस गरीब जब समझौते की बात करते हैं तो वे बचाव के बजाय परिवर्तनकारी रूख अपना लेते हैं। विस्तृत आँकड़ों की मौजूदगी से स्थानीय सरकार के लिए किसी भी बात की पुष्टि करना आसान हो जाता है और वह यह भी जान जाती है कि उसे कब और कहाँ बीच–बचाव करना है। सर्वेक्षण से अनौपचारिक बस्ती के हर एक व्यक्ति को प्रायः पहली बार औपचारिक पहचान की प्राप्ति होती है।

भारत में गणना

20 वर्ष पहले मुंबई की सड़कों की पटरियों पर बसे लोगों के कल्याण की कोई नीति नहीं थी – कोई भी इनकी मौजूदगी को मान्यता नहीं देता था। हर रोज़ इनकी झुग्गी तोड़ दी जाती थी लेकिन एक बात स्पष्ट थी, कि शहर का काम झुग्गी तोड़ना और गरीब का काम इसे फिर से तैयार करना था। इनके बारे में पहला सर्वेक्षण 1986 में किया गया जिसने इस बात को स्वीकारा कि ''हम जो नज़र नहीं आते, हमने ऐसे संसार की रचना की, जहाँ हमारे अस्तित्व से हर कोई बेखबर था और यहाँ से ही सामुदायिक संगठन महिला मिलन की शुरूआत हुई जो अपने आंकड़ों और समझ को पूरे शहर के पटरीवासियों के पुनर्वास की नीति में रूपान्तरित करेगा। साथ ही, इस संगठन ने भारत, एशिया और अफ्रीका के शहरों का विस्तृत भ्रमण किया और गणना के काम में दूसरों की मदद की। इनका आदर्श वाक्य है –जब शंका हो, तब गणना करो।

साधन 2 : समुदाय मानचित्रण

एशिया के समुदाय संगठनों के लिए इनकी आँकड़ा–संग्रहण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग बस्ती का नक्शा बनाना है। जिसमें घर, दुकानें, वर्कशाप, पगडंडियाँ, जल बिंदु, बिजली के खंभे और समस्या–स्थल सभी पर प्रकाश डाला जाए ताकि लोगों को अपनी भौतिक स्थिति के चित्रित विचार प्राप्त हो सकें। मानचित्र तैयार करना, महत्वपूर्ण कौशलपूर्ण कार्य है खास कर तब जब इसे बस्ती के सुधार और विकास अंतःक्षेपों के निर्धारण हेतु तैयार किया जाए। उदाहरणतः थाईलैण्ड में, नहर किनारे बसे समुदायों ने अपनी पुनर्वास योजना के भाग के रूप में अपनी बस्तियों का मानचित्रण किया और फैक्ट्रियों, अस्पतालों, रेस्तरां और सीवर से उत्पन्न प्रदूषण का पता लगाने तथा उनके मानचित्र बनाने का काम भी किया। इन समुदायों ने ऐसे कौशलों को अन्य नहर आवासियों से सीखा था। प्रदूषण पर विस्तृत, सटीक एवं नवीन जानकारी से भरे यह मानचित्र नियोजन एवं एकजुट होने का सशक्त साधन थे और नहरों के किनारे बसे लोगों पर नहरों को प्रदूषित करने का आरोप लगाने वाले अधिकारियों के साथ सुरक्षित भूमि धारणाधिकार पर तोल–मोल करने का प्रभावशाली साधन भी बने।

चित्रः एसीएचआर

साधन 3 : सामुदायिक बचत एवं ऋण

एशिया के समुदाय नेटवर्कों, परिसंघों और संगठनों में सामुदायिक बचत, इन सभी की वृद्धि एवं सफलता का सबसे बुनियादी तत्व बन गया है। निर्धन लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दृष्टि से यह कहना कोई अतिश्याक्ति नहीं है कि सामूहिक बचत एवं ऋण कार्यक्रमों से एशिया के समुदाय संगठनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। निर्धनों के लिए सामूहिक बचत क्यों महत्वपूर्ण है?

1 **गरीबों के लिए अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने का यह आसान एवं सीधा रास्ता है-** समुदाय संचालित बचत एवं ऋण कार्यक्रमों से समुदाय के लोग नियमित रूप से मिल कर काम करने लगते हैं और ऐसे ज़रूरी कामों के बारे में मिलजुल कर फैसले लेते हैं जिसका असर उनके जीवन पर पड़ता है। यह ऐसा तंत्र बन जाता है जिसकी जड़े साधारण एवं नियमित रीति–रिवाजों में निहित होती हैं और जिसका सरोकार समुदाय की रोज़ाना ज़रूरतों से होता हैं। सामूहिक बचत गरीबों को ऐसा संसाधन–आधार देती है जिसे वे नियंत्रित करते हैं, एक–दूसरे के जीवन के बारे में जान पाते हैं, मिलजुल कर प्रबन्ध करने और वित्तीय दृष्टि से मज़बूत होने के लिए बाहरी पद्धतियों से जुड़ना सीख पाते हैं।

2 **यह समुदाय संगठनों के निर्माण की प्रभावशाली राह है-** बचत, शहरी गरीब समुदायों एवं बस्तियों में विस्तृत स्व–विकास प्रक्रिया को विकसित करने का ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत गरीब स्वयं (और गरीब समुदायों के बड़े नेटवर्क) धीरे–धीरे आत्मविश्वास, प्रबंधकीय क्षमता और ऐसे मानदण्ड विकसित करते हैं जिससे वे औपचारिक पद्धति से जुड़ सकते हैं और वृहद् शहरी विकास प्रक्रिया में सुदृढ़ भूमिका निभा सकते हैं।

3 **इससे सहयोग, आपसी सहायता एवं सामूहिक कार्रवाई करने की संरचना पनपती है** - लोगों को नियमित आधार पर एक–दूसरे से जोड़ कर बचत, गरीब व्यक्तियों को पट्टेदारी सुरक्षा, आवासीय समस्याएं, बुनियादी सेवाएं, रोज़ी–रोटी कमाने और कल्याण जैसी गरीबी की वृहद् समस्याओं से जूझने के लिए एकजुट हो कर काम करने में सहायता करती है। इन सभी जटिल विकास कार्यों की देखरेख के लिए ढाँचे का निर्माण कर, बचत समूह; समुदाय के सर्वांगीण विकास में सहयोग देने में सहायक हो सकते हैं।

4 **इससे शक्ति एवं धन का निर्माण होता है** - वैयक्तिक बचत समूहों के लिए अपने समुदाय की बहुत सी अंदरूनी ज़रूरतों को पूरा करना तथा समुदाय संगठनों के लिए बिना बचत के एक साथ काम करना और जन शक्ति को सीमित क्षेत्र तक संगठित करना भी संभव हो सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बचत एवं ऋण के कारण आपके पास धन और शक्ति दोनों होंगे, जो गरीब के जीवन को बेहतर बनाने के दो अनिवार्य तत्व हैं।

5 **यह वृहद् विकास परियोजनाओं को पूरा करने का कौशल निर्मित करती हैं** - बचत से ऐसी संयुक्त प्रबंधकीय क्षमताएं विकसित होती हैं जो अपनी म्यूनिस्पिल सरकारों की भागीदारी में काम करने हेतु समुदायों के लिए ज़रूरी हैं। बचत को दर्शाती सामूहिक परिसंपत्तियाँ आवास और विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी एजेंसियों से समझौते की बातचीत करने और औपचारिक पद्धति से जुड़ने तथा समुदायों के लिए तोलमोल करने का सशक्त साधन बन जाती हैं। *(आवासीय वित्त पर तत्काल गाईड–5 देखिये)*

स्त्रोत : यूसीडीओ अपडेट न.2, अक्तूबर 2000. डाउनलोड फ्राम www.codi.or.th

चित्रः एसीएचआर

''वित्त मंत्रालय'' से रहित देश ऐसा है जैसे कि खून के बिना शरीर। इसी तरह, गरीब समुदाय के लिए अपने धन की देखरेख करने और अपने जीवन की बेहतरी हेतु ज़रूरी निर्णय लेने के लिए आपसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए अलग वित्त अनुभाग स्थापित करना ज़रूरी होता है।

सोमसूक बूनीबंचा, सीओडीआई, थाईलैण्ड

भिखारी का जीवन अब और नहीं

जो समुदाय अपनी निजी बचत के साथ समझौते पर बातचीत करने आते हैं, वे अपने शहरों के साथ 'समान भागीदार' के रूप में काम करने की स्थिति में होते हैं

जब बहुत से बचत समूह एक–दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वृहद बचत समूह नेटवर्क के माध्यम से ये बड़े वित्तीय संसाधनों तक पहुँच बना कर समझौते की बातचीत कर सकते हैं। बचत समूह गरीब समुदाय संगठनों को सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने के योग्य बनाते हैं क्योंकि जब लोग निजी संसाधनों से संपन्न और स्वयं नियंत्रक भी होते हैं तो उनकी स्थिति भिखारी का जीवन जीने वाली नहीं रह जाती अपितु वे अपने लिए मन चाहे विकास हेतु निर्णय ले सकते है।

इस प्रक्रिया के राजनीतिक निहितार्थ हैं क्योंकि इन बचत नेटवर्कों की मज़बूत स्थिति, गरीबों को ऐसे वृहद् संरचनागत मुद्दों से निपटने के योग्य बनाती है जो इन समस्याओं का आधार हैं। इन नेटवर्कों की वृद्धि के साथ, ये स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों के लिए आवासीय, पट्टेदारी, बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण एवं कल्याण जैसी समस्याओं के हल खोजने के लिए लाभप्रद विकास भागीदार बन जाते हैं। सामुदायिक बचत समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय पद्धतियों के बीच की दूरी को भरने में भी सहायक हो सकते हैं। गरीब समुदायों में आवासीय ऋण और भूमि एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को भी अब बहुत से देशों में सुस्थापित बचत समूहों के माध्यम से चैनलबद्ध किया जा रहा है।

दैनिक बचत

रोज़ाना बचत की शुरूआत सर्वप्रथम भारत और साऊथ अफ्रीका में हुई। लेकिन तभी से इस विचार का प्रसार पूरे एशिया में हो गया। बहुत से गरीब समुदाय संगठनों के लिए रोज़ाना की बचत कैसे कारगर है? दैनिक बचत, बचत समूह को समुदाय में नए बदलाव लाने में सहायता करती है। लोग दैनिक आधार पर एकसाथ काम करते हैं और मासिक बचत की तुलना में अधिक गहरे दैनिक रिश्ते में बँध जाते हैं, मासिक रिश्ते में लेन–देन सिर्फ एक दिन और बाकी के 29 दिनों की छुट्टी जबकि दैनिक बचत समुदाय उन सबसे गरीब लोगों के लिए भी आकर्षण है जो दैनिक आधार पर कमाते हैं और जिन्हें मासिक बचत के कारण कठिन समय से गुजरना पड़ता है। साथ ही, जब लोग दैनिक बचत करते हैं तो रोज़ ही ऋण के भाग को चुकता भी करते हैं तो इसका अर्थ है कि भुगतान की राशि कम होती है और बड़े मासिक भुगतान से खौफनाक भी कम होती है। इसलिए, इससे ऋण अदा करना अधिक आसान हो जाता है और अदायगी समस्याओं का निपटान करने में सहायता मिलती है।

स्त्रोतः www.codi.or.th

साधन 4 : समुदाय नेटवर्क निर्माण

इधर–उधर बसे हुए लघु पैमाने के बचत एवं ऋण समूह जब विकसित एवं परिपक्व होने लगते हैं तो सदैव अन्य समूहों से स्थायी रिश्ते में बँध जाते हैं और एक किस्म का संयुक्त (वित्तीय या संगठनात्मक) आधार वाला बड़े पैमाने का नेटवर्क स्थापित कर लेते हैं। नेटवर्क वैयक्तिक समुदायों को गतिशील सहयोग प्रदान करते हैं और एक–दूसरे के अनुभव बाँटने तथा एक–दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे संसाधनों को एकजुट करना भी संभव हो जाता है। इस प्रकार के सहयोग से समूह बेहतर वित्तीय संसाधनों तक पहुँच स्थापित कर पाते हैं और उनमें अखंडता की भावना पनपने लगती है। वे पूरे आत्मविश्वास से अपने हक एवं ज़रूरी संसाधनों की प्राप्ति के लिए राज्य एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ समझौते की बातचीत करने की स्थिति में आ जाते हैं।

इस प्रक्रिया के राजनीतिक निहितार्थ हैं क्योंकि अधिक मजबूत नेटवर्कों के गठन से निर्धन अपनी समस्याओं से संबंधित बड़े एवं संरचनागत मुद्दों से निपटने के योग्य बन जाते हैं, जिनसे छोटे और एकाकी समुदायों के रूप में निपटना, पहले उनकी क्षमता से परे था। नेटवर्क से गरीब लोग बेहतर ढंग से तोलमोल कर पाते हैं और एक ऐसी व्यावहारिक, स्व–संचालित समुदाय विकास प्रक्रिया को दर्शाते हैं जो कि उनके उत्थान से जुड़े ऐसे नगरीय कार्यों को करने की क्षमता रखती है जिन्हें पूरा करना, मौजूदा पद्धतियों एवं संस्थान की क्षमता से परे है।

आगे बढ़ने की राह का अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि एकल व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय यदि मिलजुल कर काम करेंगे तो ये ही अपनी समस्याओं के निपटान की योजना बनाने में सफल होंगे। जब तक सारे समुदाय समस्याओं के निपटान के लिए बदलाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक वे अच्छे विकल्पों को तलाशने के संबंध में अपने मुखिया को भलीभांति सशक्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए, हमें ऐसी अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता है जो सभी समूहों को अपनी और आकृष्ट करें और समूचे समुदायों के दृष्टिकोण को विकसित करें। वृहद् समुदाय नेटवर्क से ऐसी अध्ययन पद्धति की प्राप्ति होती है।

संसाधनों एवं इन्हें प्राप्त करनेवालों के बारे में ज़रूरी बात

गरीब लोगों के लिए (भूमि, घर, बुनियादी सेवाओं एवं वित्त तक पहुँच) आदि जैसे संसाधन, परमावश्यक हैं, और यह बात महत्वपूर्ण नहीं है आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। संसाधन राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करते हैं। यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति से आशय् है कि शहर में किसकी कितने संसाधनों तक पहुँच है। कोई भी समुदाय एकल प्रयासों से इन चीजों की प्राप्ति के लिए शहर से तोलमोल नहीं कर सकता। जब सभी एकजुट होकर अर्थात्, भारी संख्या में संयुक्त बल से जब समझौते की बात करते हैं तो बदलाव आता है। एक सबसे महत्वपूर्ण सीख जो एशिया के समुदाय समूहों ने ली है, वह है कि बदलाव लाने की निरंतर माँग करने वाले 'महत्वपूर्ण जन समूह' का गठन अत्यावश्यक है। सरकार के पास अशक्त समूहों से निपटने के लिए न कोई विशेष साधन हैं और न ही सरकार की कोई ऐसी मंशा है और गरीब लोगों की तरफ से बदलाव की माँग करने के लिए इस संबंध में निर्मित सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन भी दरकिनार नज़र आते हैं। आपको समस्या का हल ढूँढ़ रहे, विभिन्न संदर्भों में विकल्पों, प्रतिभागिता और विश्वास का पैमाना निर्मित करने हेतु अनेक प्रयोग कर रहे ढेरों लोगों की जरूरत है। जब हज़ारों लोग एक सी बातों की प्राप्ति के लिए समाधानों की तलाश करते हैं तो महत्वपूर्ण जनसमूह समाधानों की सृजना करता है और बदलाव का विरोध करने वाली कड़ी को तोड़ देता है तथा गरीबों एवं संसाधनों के बीच के अवरोधों को समाप्त कर देता है।

चित्र: यूएसएआईडी फायर प्रोजेक्ट

स्त्रोत : फेस–टू–फेस, एसीएचआर

साधन एवं दिशानिर्देश

4 तरीके जिनसे नेटवर्क एशिया के समुदाय आंदोलनों में बदलाव ला रहे हैं :

पिछले बीस वर्षों में, एशिया के समुदाय नेटवर्क एवं परिसंघ ऐसे महत्वपूर्ण विकास तंत्र बन गए हैं जिनका सीधा सरोकार गरीबों से है और जो अपने सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान तलाश सकते हैं। शहर–व्यापी विकास परियोजनाओं की शुरूआत करने और विस्तृत शहर विकास नीतियों को प्रभावित करने के लिए अन्य सिविल समूहों के सहयोग से काम करने के लिए, नेटवर्कों ने शहरों के सहयोग से काम करने की शुरूआत की है। शहरी गरीब और औपचारिक पद्धति के बीच दृष्टिकोण संबंधी कमियों को दूर करने और बहुत से तरीकों से इस महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध को संतुलित करने में, समुदाय नेटवर्कों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है :

1 **समुदाय आंदोलनों के पैमाने में बदलाव :** नेटवर्क मॉडल में, एकल समुदाय सबसे छोटी संरचनागत इकाई और सर्वाधिक स्थानीय– क्षेत्र है। लेकिन जब ये शहर, प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर आपस में जुड़ जाते हैं तो राजनीतिक बल नज़र आते हैं। इन दो मूलतत्वों – आधारिक रूप से एकल समुदाय और अनेकों के बल से लैस बड़े सामूहिक नेटवर्क अर्थात् इनके बिना आप किसी भी महत्वपूर्ण पैमाने पर संरचनागत बदलाव लाने की आशा नहीं कर सकते। नेटवर्क, समुदाय की तरफ से ऐसी बातों के लिए तोलमोल कर सकता है जहाँ समुदाय अपने लघु अस्तित्व के कारण स्वयं ऐसी बातों को पूरा नहीं कर सकते।

2 **गरीबी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले दृष्टिकोण में बदलाव :** अधिकांश विकासात्मक कार्यों में राज्य, विकास एजेंसियाँ और गैर सरकारी संगठन, संसाधनों को नियंत्रित करते हैं और हर ज़रूरी फैसला लेते हैं। इस संबंध में लोगों की मनमानी नहीं चलती और उन्हें वही करना पड़ता है जो दूसरों ने उनके लिए निर्धारित किया होता है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें हर लाभ से वंचित होने का जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन नेटवर्कों के साथ, गरीब लोग जो सीखना चाहते हैं, उन्हें उसे सीखने की स्वतंत्रता होती है। इनके माध्यम से वे विकल्पों की छानबीन कर सकते हैं और विवेकपूर्ण विकल्पों को अपना सकते हैं। समुदाय नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकास के लिए शक्तिशाली मंच प्रदान करते हैं और इससे समुदाय–चालित विकास प्रक्रमों को बड़े पैमाने पर स्वीकारा जाता है।

3 **समुदाय के आपसी संबंधों में बदलाव :** पारम्परिक ''अधोगामी विकास'' में विकास एजेंसियों और एकल समुदायों के बीच कड़ियाँ उर्ध्वाधर हैं। जब समस्याएं आती हैं तो समुदायों के बीच आपसी सहायता के क्षैतिज तंत्र के अभाव के कारण लोग मदद के लिए निरंतर संस्थानों पर आश्रित बने रहते हैं। लेकिन सूचना चैनल के रूप में नेटवर्कों से लोग निरंतर एक–दूसरे से सीखते हैं और समान गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। जब एक समुदाय कोई कारगर दृष्टिकोण विकसित कर लेता है तो नेटवर्क के अन्य समुदाय नियमित कार्यविधि के रूप में उस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं।

4 **समुदायों में आंतरिक संतुलन तंत्रों का विकास :** नेटवर्क, समुदायों को अपनी आंतरिक समस्याओं को निपटाने के बहुत से साधन प्रदान करते हैं और संतुलित, साम्य, समुदाय–चालित विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए समुदायों पर निगाह बनाए रखते हैं और इनके कार्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करते हैं। पहले जब समुदाय समस्याग्रस्त होते थे तो वे उन्हीं में उलझ कर रह जाते थे। लेकिन नेटवर्क हर प्रकार की समस्या अर्थात जिस पर सभी अपने विचार प्रकट करें, ऐसी समस्याओं के लिए बड़ा मंच प्रदान करते हैं। ऐसी शुरूआत महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र, समन्वय स्थापित करने, तनाव दूर करने और आत्म सम्मान को बनाए रखते हुए समस्या–निपटान का उचित मार्ग नज़र आ सकती है।

स्त्रोत : www.codi.or.th

चित्र: एसीएचआर

पुराने सिक्के को नया रूप देना ज़रूरी नहीं

आदान–प्रदान का सबसे शक्तिशाली पहलू है कि इससे ढेरों विकल्पों की प्राप्ति होती है। लोगों के लिए हर सिस्टम स्वयं विकसित करना ज़रूरी नहीं होता। वे आवश्यकतानुसार दूसरों से ऐसी प्रक्रिया की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे वृहद् एशियाई अनुभव आदान–प्रदान प्रक्रिया कहते हैं।

साधन 5 : जन–से–जन तक ज्ञान का आदान–प्रदान

विकास की राह का हमेशा से यह मिथक है कि निर्धन के जीवन और इनकी बस्तियों में कोई सुधार नहीं हो रहा क्योंकि इनमें सुधार लाने के कौशलों की कमी है और यदि इन्हें इन कौशलों में पर्याप्त प्रशिक्षण मिल जाए तो ये अवश्य फले–फूलेंगे। लेकिन ऐसे जटिल मुद्दे जो गरीबों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने और भू, आवास, सेवा एवं वित्त तक पहुँच बनाने से रोकते हैं, किसी भी प्रबंधकीय या तकनीकी कौशलों से परे के मुद्दे हैं और हमारे समाजों में बहिष्कार, असमता और अन्यायपूर्ण नियोजन की गूढ़ संरचनागत समस्याओं पर आधारित हैं।

एक–दूसरे से सीखना, विकास का ऐसा साधन है जो निर्धनता और गृहहीनता के मूल मुद्दों से निपटने में निर्धन लोगों की क्षमताओं का निर्माण करता है और जिससे ये स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निजी साधनों का निर्धारण कर सकते हैं।

जब गरीब लोग, दूसरी जगहों के गरीब लोगों से मिलते हैं जो कार्यों को करने में किसी भी पेशेवर से ''प्रशिक्षित'' नहीं होते, तो इन्हें कोई नहीं बताता कि क्या सीखा जाए और कब सीखा जाए। लोग खुद ही जो सीखना है, सीख लेते हैं और अन्य बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वह महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसकी प्राप्ति सीधे स्त्रोत से होती है।

समुदाय–से–समुदाय शिक्षा का आदान–प्रदान, बेहद उपयोगी एवं बहुपक्षीय विकास के साधन के रूप में उभरा है जो पूर्णतया गरीबों को समर्पित है। आत्मविश्वास और विकल्प बढ़ाने तथा नेटवर्क निर्माण में वृद्धि करने वाला क्षैतिज सामुदायिक विनिमय एशिया के निर्धन समुदायों में निराशा और लाचारी से उभरने की सबसे सशक्त दवा है। ज्ञान विनिमय एक दूसरे से सम्वाद स्थापित करने, समस्याओं का परीक्षण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, समस्याओं का समाधान एवं एक दूसरे को सहयोगी के रूप में प्रयोग करने की गरीबों के संगठनों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

> गरीब लोगों के पास कौशल, विचार और श्रेष्ठ विकल्पों के बीज होते हैं। लेकिन उनके पास जो नहीं है, वह है – इन सभी को व्यावहारिक रूप देने की पर्याप्त जगह और इनकी छानबीन करने और इन्हें उत्कृष्ट रूप देने में सहयोग का अभाव।

स्त्रोत : एसीएचआर, ''फेस टू फेस''

आदान–प्रदान कोई नई बात नहीं है

दूर बसे समान दृष्टिकोण वाले लोगों से जुड़ाव रखना, मनुष्य की पुरानी ललक है, लेकिन निर्धन के लिए आसान नहीं है।

पेशेवर शिक्षाविद्, प्रशासक और उद्यमी, आपसी बातचीत, विचारों के आदान–प्रदान और दूसरों के परिप्रेक्ष्यों को आत्मसात् करने के लिए आपस में मिलते–जुलते हैं। हमउम्र लोगों से विचारों का आदान–प्रदान, पेशेवर जीवन का स्वभाव माना जाता है। गरीबों को अपनी बस्तियों से बाहर विचारों के आदान–प्रदान का अवसर नहीं मिलता, इसलिए गरीबी इन्हें समाज में अलग–थलग कर देती है।

बावजूद इसके, यदि आप गरीब समुदायों के इर्दगिर्द नज़र डाले तो आपको निर्माण, नवीनता, तोलमोल करना, सीखना और आगे बढ़ने जैसी अनेक बातें नज़र आएंगी। एशियाई ज़मीनी स्तर के संगठन, नवीनतम जन–चालित विकल्पों पर केंद्रित हैं और शक्तिशाली कौशलों एवं अनुभवों को दर्शाते हैं। पंद्रह वर्ष पहले हर कोई ऐसे कार्यों से अनभिज्ञ था – ये सभी संघर्ष एकाकी घटनाएं थी। यहां से क्षैतिज आदान प्रदान शिक्षा शुरू होती है। समाधान जब एक जगह कारगर होता है तो आदान–प्रदान से अधिक अवसर सृजित होते है जिससे वे नई बाते सीखते हैं और अनुभव का आदान–प्रदान करते हैं और इस तरह अच्छे विचारों का प्रसार होता है। आमतौर पर इसका अर्थ है कि समुदाय लीडर (और कई बार सरकारी अधिकारी) व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्राप्ति हेतु बाहर जाते हैं और जब लौटते हैं तो घर एवं अन्य शहरों के लिए संदेश लेकर आते हैं। ये राष्ट्रीय समूह जितना अधिक क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को आत्मसात करते हैं, उतने ही क्षेत्रीय तंत्रों का निर्माण होता है जिससे नई कोपलें फूंटती हैं।

ज़मीनी स्तर के समूहों की बढ़ती संख्या और समर्थकों ने इस प्रकार की प्रत्यक्ष एवं अनुभवजन्य शिक्षा को अपना लिया है। गत् 20 वर्षों से अभिव्यक्तीकरण की इस प्रक्रिया ने बढ़त एवं परिपक्वता की प्राप्ति की और विविध रूपों में विस्तारित हो गई। आदान–प्रदान इस क्षेत्र की सहज विशेषता है – कि अधिकतर एशियाई समुदाय एवं परिसंघ और इनकी क्षेत्रीय कड़ियाँ किस प्रकार काम करती हैं और किस प्रकार गरीब सीखते हैं।

जन-से-जन तक ज्ञान-का आदान-प्रदान, किस प्रकार वैश्विक स्तर पर भी काम कर रहा है।

एशिया और अफ्रीका के बहुत से समुदाय संगठनों के लिए स्लम–डवेलर इंटरनेशनल नेटवर्क में शामिल होना एक ऐसा सहज प्रगतिशील कदम है और इनके शहरों, देशों एवं क्षेत्रों में पहले से ही ज्ञान का आदान–प्रदान कायम है। एसडीआई सदस्य विचारों के आदान–प्रदान और सहयोग देने के लिए नियमित रूप से आपस में मिलते हैं और इसी आधार पर निरंतर ज्ञान–विनियम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया जिस किसी भी रूप में उभरे, शहरी निर्धनों को अधिकाधिक लाभ होता है।

पिछले दस वर्षों से, एसडीआई ने भूमि, आवास, बुनियादी सेवाएं और रोज़ी–रोटी की समस्याओं से जूझने के लिए अपनी खुद की रणनीति को विकसित एवं स्पष्ट करने के लिए वैश्विक स्तर पर जन संगठनों के सुदृढ़ संघ बनाने का प्रयास किया है ताकि ये समूह अपनी समझबूझ एवं अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकें। नेटवर्क ने विश्व के विभिन्न भागों शहरों में कुछ ऐसे वर्तमान जीवंत उदाहरणों को पेश किया है जहाँ समुदायों ने सुरक्षित भूमि और तत्पश्चात् बुनियादी ढाँचे एवं आवासों के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की है।

एसडीआई जैसे ज़मीनी स्तर समूहों के वैश्विक नेटवर्क से भूमि और घरों की गंभीर समस्याओं से जूझते समुदाय यह जान पाते हैं कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं और उन जैसे और भी समुदाय हैं जो समान समस्याओं से जूझ रहे हैं और समस्याओं के निपटान के रास्ते तलाश रहे हैं। इस तरह समुदाय ऐसे बहुत से विकल्पों या रणनीतियों को चुन सकते हैं जो फिलहाल उनके तात्कालिक परिवेश में शायद उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन्हें कहीं और तैयार, जाँचा एवं परखा जा चुका है।

स्त्रोत : एसीएचआर

साधन 6 : वैकल्पिक योजनाएं तैयार करना

गरीबों को जब अपने अधिकारों की माँग करने और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सहारा या समर्थन दिया जाता है तो इससे अधिकारियों के समक्ष दो विकल्प होते हैं कि: वे उनकी बात को स्वीकारें या फिर इसे नामंजूर कर दें। ऐसी स्थिति लगभग सभी समुदायों के लिए अंधी गली के समान होती हैं। लेकिन तब बात कुछ और होती है जब समुदाय संगठनों के पास ऐसे वर्ग के लिए रणनीतियाँ विकसित करने और उनमें सुधार लाने के संभावित विकल्प एवं अवसर उपलब्ध होते हैं और तब, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाएं, वे राज्य से संवाद स्थापित करने की शुरूआत कर देते हैं।

समुदाय संगठनों को विकास के भागीदार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने का एक श्रेष्ठ तरीका, अपनी शहरी सरकारों को जन–समर्थित अच्छे वैकल्पिक विचारों से अवगत कराना है। यह विशेष रूप से वहां ज़रूरी होता है जहां समुदायों को विचाररहित एवं कौशलरहित माना जाता है और जिनके पास देने को कुछ नहीं होता और जो तोलमोल नहीं कर सकते। जब समुदाय समय से पहले अपनी समस्याओं के निपटान की तैयारी कर लेंगे तब उनके पास अधिक विकल्प मौजूद रहेंगे और वे स्थिति को भलीभांति नियंत्रित भी कर पाएंगे। इस तरह वे रक्षात्मक की बजाय आक्रामक होंगे

जब गरीब समुदाय अपने निजी, विस्तृत एवं यथार्थवादी आवासीय विकल्पों के साथ समझौते की बातचीत के लिए आते हैं तो स्थानीय अधिकारियों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है।

यथापूर्व स्थिति से आगे की ओर बढ़ना

अधिकतर मामलों में समस्या यह है कि समुदाय एवं नगरीय सरकारों की मानसिक स्थिति समझौते की बातचीत करने की नहीं होती। दोनों एक–दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और स्वयं को ऐसे सामंतवादी संबंध में बाँध लेते हैं जहाँ सरकार का रूख ऐसा होता है जैसे वही हर बात श्रेष्ठ ढंग से जानती है। यह हमारे देश में हर जगह व्याप्त है जहाँ समुदाय एवं इनके गैर सरकारी संगठन समर्थकों का निरंतर मानना है, "यह काम हम क्यों करें?" "इसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है" और जब राज्य इसे करता है तो समुदायों को इनकी कार्रवाई पसंद नहीं आती और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जब राज्य ऐसा काम करने में सक्षम न हो या ऐसा प्रबंध न कर पाएं तो आप क्या करेंगे?

विभिन्न समूह, इस प्रतिमान से अलग–अलग तरीकों से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक मामले में सफलता तभी मिलती है जब हर कोई समझौते की बात के लिए सामने आता है और जब समुदाय अपने मुद्दों के संबंध में पूरी तैयारी करके आते हैं और इस संबंध में अपनी वैकल्पिक योजनाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति में होते हैं। समुदाय की इस

चित्र: सीओडीआई

प्रकार की तैयारी में बचत करना, अपनी बस्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, सर्वेक्षण करना, विचारों के आदान–प्रदान से अपनी क्षमताओं का निर्माण करना और नेटवर्क निर्माण के माध्यम से अपने सामूहिक गठबंधन को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। राज्य के साथ समझौते की बातचीत करने का सबसे शक्तिशाली साधन ऐसी वैकल्पिक योजनाएं हैं जो लोगों द्वारा निर्मित हैं और जिससे लोगों की भूमि, आवासीय आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का पता चलता है।

स्त्रोत : फेस टू फेस, एसीएचआर

साधन एवं दिशानिर्देश

शहर को अपने जल मार्गों एवं बाढ़ नियंत्रण पद्धतियों के रखरखाव में निःशुल्क सहायता की प्राप्ति होती है और समुदायों को सुरक्षित भू–धारणाधिकार, बेहतर जीवन यापन परिवेश एवं बेहतर घरों की प्राप्ति होती है। सभी को लाभ होता है और ये विचार किसी पेशेवर योजनाकार या सरकार के नहीं हैं बल्कि लोगों के अपने विचार हैं।

चित्रः एसीएचआर

चियांग मॉय, (थाईलैण्ड) में वैकल्पिक नियोजन

थाईलैण्ड के अधिकतर शहर नहरों एवं निम्न दलदलीय क्षेत्रों के आसपास बसे हैं और जो कि जल नियंत्रण में सहायक है और इस वजह से पारंपरिक रूप से वाणिज्य, परिवहन एवं विकास के मार्ग खुले हैं। लेकिन ये नहरें अब जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और इनमें शहर का कूड़ा भरा हुआ है और गंदा पानी खड़ा है और इनके किनारे बसे लोगों पर ही इन्हें दूषित करने का आरोप मढ़ा जाता है और घर खाली कराने की धमकी अक्सर मिलती–रहती है।

वर्ष 1999 में चियांग मेइ की मेखा (Maekhaa) नहर के किनारे बसी बस्तियों के नेटवर्क ने म्यूनिसिपैलिटी से वर्षों से जगह खाली कराने के लिए जो भी धमकियाँ या अपमान मिलता था, उसे नकारते हुए, अपनी बस्तियों एवं नहर के उत्थान के लिए स्वयं वैकल्पिक योजनाओं को विकसित किया।

इन समुदायों ने नियमित उच्च स्तरीय सफाई–पर्वों के आयोजन से शुरूआत की जहाँ हर कोई नहर की साफ–सफाई के लिए आगे आया। सीओडीआई के सहयोग से इन समुदायों ने उचित पैदल पथों एवं जलनिकासी लाइनों सहित अपनी बस्तियों में लघु पर्यावरणीय सुधार लाने की शुरूआत की। इन प्रारंभिक सुधारों और शहर से प्राप्त सकारात्मक समर्थन ने बस्ती से जुड़ी विस्तृत सुधार योजनाओं को विकसित करने के लिए समुदायों में आत्मविश्वास की भावना जागृत कर दी।

कुछ समुदायों में स्थानीय निवासियों ने शहर की नहर के डी–सिल्टिंग बैराजो के लिए रास्ता बनाने हेतु, स्वेच्छा से अपने घरों को पीछे हटा लिया है और नहरों के किनारे बड़े उद्यान एवं सार्वजनिक पैदल पथ विकसित किए हैं। स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया में म्यूनिस्पल और निजी क्षेत्र प्रदूषकों के साथ मिलकर समुदाय–आधारित ''ग्रीन'' वाटर फिल्टरिंग सिस्टम विकसित करना और बाहरी प्रदूषण को नहर में मिलने से रोकना तथा अपनी नहरों के प्रबन्धन एवं सुरक्षा को नियन्त्रित करने वाले अन्य थाई शहरों के दौरे करना भी शामिल था।

वैकल्पिक योजनाओं और इसमें सम्मिलित गतिविधियों के जरिए नेटवर्क दर्शाते हैं कि ये नहर को दूषित करने वाले नहीं हैं बल्कि नगरीय नहरों की स्वच्छता, देखरेख एवं नया जीवन देने में शहर के श्रेष्ठ सहयोगी हैं और उस प्रक्रिया से धीरे–धीरे वहीं बसे रहना, उनका अधिकार बन जाता है।

स्त्रोत : www.codi.or.th

समुदाय विकास निधियाँ

गरीब समुदाय संगठनों को इनकी अपनी शर्तों पर और इनकी निजी पहल को सहयोग देने हेतु वित्त वितरण का सरल एवं लचीला तरीका

समुदाय विकास फंड (सीडीएफ) का सरोकार ऐसे विविध प्रकार के संस्थानों से है जिनका गठन गरीब समुदायों को ऋण एवं अनुदान देने के लिए हाल ही में बहुत से एशियाई देशों में किया गया है। ये सभी फंड, विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं, क्षमताओं और राजनीतिक संदर्भ पर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से तरह–तरह के हैं (आवासीय वित्त पर तत्काल गाईड–5 देखिये)। इन फंडों में से कुछ की शुरूआत सरकारों ने की है जबकि कुछ की स्थानीय सरकारों के भागीदारों के रूप में गैर सरकारी संगठनों या समुदाय परिसंघों ने की है। ऋण के रूप में दी जाने वाली पूँजी, सहयोग प्रदाताओं, सरकारों, सामुदायिक बचत एवं वित्त संस्थानों से प्राप्त की जाती है। इन सभी में सामान्य है, कि ये बेहद सरल एवं लचीले किस्म के ऋण हैं और इनका संचालन समुदायों, स्थानीय अधिकारियों एवं अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये समुदाय संगठनों की आवासीय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करने एवं आय–जनन के लिए परमावश्यक ऋण प्रदान करते हैं। सीडीएफ, निर्धन समुदायों को पूँजी दिलाने का ही तरीका नहीं है बल्कि सीडीएफ दृष्टिकोण के अन्य बहुत से लाभ हैं :

1 **धन को जन की असल ज़रूरतों को ध्यान में रख कर पद्धति से आकर्षित जाता है, न कि बाहरी विकास एजेंडे के ज़रिए ''प्रतिकर्षित किया'' जाता है** - अधिकतर सामुदायिक फंड, ऐसी वित्तीय एवं संगठनात्मक परिसंपत्तियों पर आधारित होते हैं जिन्हें सामुदायिक बचत से पैदा किया जाता है, और ज़रूरतों एवं परियोजनाओं का निर्धारण लोगों द्वारा किया जाता है : ये समुदाय काम करते हैं और धन की भी देखरेख करते हैं; न कि एजेंसियों या पेशेवर या गैर सरकारी संगठन।

2 **ये अक्सर सीधे गरीबों के लिए विकास संसाधनों की प्राप्ति के आसान, लचीले एवं अधिक बेहतर तरीकों की पेशकश करते हैं** और इन सभी कामों में लाल फीताशाही और महँगी विकास लागतों की गुंजाइश नहीं होती जो परंपरागत विकास परियोजनाओं से जुड़ी होती है। जब समुदायों को काम और धन दोनों की देखरेख में शामिल किया जाता है तो उपलब्ध कौशलों के भरपूर प्रयोग और लागतों को न्यूनतम करने वाली संतुलित एवं कारगर पद्धतियों की शुरूआत होती है।

3 **ये लोगों को वित्तीय एवं राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति का साधन प्रदान करते हैं** - फंड, जन की पहल को सुदृढ़ कर सकते हैं, विशेष रूप से जब वे अपनी सरकारों से समझौते की बातचीत करते हैं तो संसाधनों एवं संस्थागत शक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं और लोगों को आवश्यक बदलाव लाने के लिए पद्धति के विविध स्तरों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने के लिए लोगों की सहायता करते हैं।

4 **ये पारदर्शिता एवं जवाबदेही के निर्माण में सहायता करते हैं** - समुदाय विकास का एक बड़ा अवरोध है कि लोगों को समुदाय में आने वाले धन के बारे में नाममात्र की जानकारी होती है। क्योंकि गैर सरकारी संगठन और सहयोग प्रदाता एजेंसियों का ही इन पर कब्जा बना रहता है और इस वजह से समुदाय सहभागी की बजाय मात्र प्राप्तकर्ता ही बना रहता है। लेकिन जब हर किसी को पता होता है कि 'कितना धन कहाँ है' तो पूरा संबंध ही बदल जाता है। सहभागिता से आशय् सिर्फ धन नियंत्रण से नहीं है। यदि समुदाय अपनी बचत को बढ़ा कर, एकत्र करके निधियों की देखरेख पूरी पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारी से करता है तो वह सशक्त हो जाता है।

5 **ये दीर्घकालिक हैं** - विकास अल्पकालिक नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है और बदलाव में वक्त लगता है क्योंकि समुदाय की पूँजी, ऋण के रूप में समुदाय में घूमती है। इसलिए समुदाय ऋण का सहज रूप से दीर्घकालिक तंत्र है। ये समुदाय के लिए उन कामों को पूरा करने के संसाधन बन जाते हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं, भले ही उसमे कितना ही समय लगे। इसकी तुलना पारम्परिक परियोजना कोष से कीजिए जहा सम्बद्ध पैसा शीघ्र ही लुप्त हो जाता है।

थाईलैण्ड में समुदाय विकास फंड

समुदाय संगठन विकास संस्थान (सीओडीआई) की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी जब शहरी समुदाय विकास कार्यालय का ग्राम विकास फंड में विलय किया गया था। सीओडीआई, थाईलैण्ड के शहरी एवं ग्रामीण गरीब समुदायों को बहुत से तरीकों से सहयोग देता है। सार्वजनिक संगठन (सामाजिक विकास एवं मानव सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत) का दर्जा हासिल करके स्वायत्त कानूनी पहचान के साथ सीओडीआई, को परंपरागत सरकारी संस्थानों की तुलना में काफी अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है।

सीओडीआई ऐसा संस्थान है जो बड़े पैमाने पर लोगों की पहल से बदलाव लाने के नए तरीकों की प्रस्तुति करने का प्रयास कर रहा है। सीओडीआई सिर्फ गरीबी उन्मूलन पर ही नहीं बल्कि ऐसे तरीकों पर भी गौर कर रहा है जहाँ समुदाय अपनी पसन्द के विकास में मुख्य कार्यकर्ता हो सकते हैं। सीओडीआई की कार्यपद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, समुदाय के लिए कुछ खास जगह बनाए रखनी है ताकि वह ज़रूरी निर्णय स्वयं ले सकें और संस्थान को दिशा दे सकें, ताकि सीओडीआई ऐसे सार्वजनिक संस्थान के रूप में अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके है जो लोगों का अपना हो और जिसका प्रबन्धन जनता के संयुक्त सहयोग से किया जाता हो।

सीओडीआई ने अपने पहले दो वर्षों में समुदायों एवं समुदाय नेटवर्कों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने और इन नेटवर्कों के माध्यम से पहचानी गई समस्याओं के निपटान हेतु प्रांतीय एवं मुद्दा–आधारित तंत्रों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरे वर्ष में, मुख्य ध्यान, इस नव–सशक्त राष्ट्रीय जन प्रक्रिया को विविध सरकारी नीतियों का अहम् हिस्सा बनाना था। परिणामस्वरूप बहुत से कार्यक्रमों की शुरूआत की गई और जो थाईलैण्ड में निर्धनता और विकास की समस्याओं से जूझने में जन–सहभागिता की संभावना को दर्शाते हैं। ऐसे कार्यक्रम हैं :

- बान मैकांग शहर व्यापी समुदाय अपग्रेडिंग कार्यक्रम
- समुदाय नियोजन
- समुदाय आधारित कल्याण
- क्षेत्र एवं मुद्दा आधारित नेटवर्किंग
- समुदाय चालित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन

वर्ष 2000 से देश के लगभग आधे से अधिक शहरी एवं ग्रामीण समुदाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीओडीआई प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। ये कड़ियाँ स्वचालित अध्ययन तंत्र प्रदान करती हैं जो कि देश–व्यापी हैं और जहाँ लोगों को बहुत कुछ मिलने की ढेर सारी संभावनाएँ हैं।

स्त्रोत : www.codi.or.th

चित्रः सीएएसई – थाईलैण्ड

गरीब समुदायों के लिए राष्ट्रीय फंड

सीओडीआई की सक्षमता का एक महत्वपूर्ण बिंदु इन सभी पहलुओं को सहयोग प्रदान करना और इन नेटवर्कों से उभरने वाले अवसरों पर ज़रूरतों के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। फंड फिलहाल 77 मिलियन अमेरिकी डालर है जो वैयक्तिक आधार पर नहीं बल्कि समुदाय संगठनों के लिए चार प्रकार के ऋणों के रूप में समुदायों में घुमाया जाता है। ये हैं : आवास और भूमि संबंधी ऋण, समुदाय उद्यमों हेतु ऋण, सर्वांगीण विकास हेतु समुदाय नेटवर्कों के लिए ऋण और बचत समूहों या समुदाय नेटवर्कों के लिए नमनीय फन्ड्स

समुदाय संगठनों को सहयोग देने के 10 तरीके

1 गरीबों या इनके संगठनों को प्रभावित करने वाली किसी भी नीति, योजना, कार्यक्रम या परियोजना निर्माण में गरीबों की पूर्ण सहभागिता सदैव सुनिश्चित करें।

2 याद रखें कि सभी शहरी गरीब एक समान नहीं हैं। शहरी गरीबी, महिला, पुरुष, बच्चों, युवाओं एवं वृद्धों को भिन्न–भिन्न तरीके से प्रभावित करती है। विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों और समुदायों के लोगों की भिन्न–भिन्न ज़रूरतें, समस्याएं एवं प्राथमिकताएं हो सकती हैं और इनकी गरीबी का स्तर भी एकसमान नहीं होता।

3 गरीब जन समुदाय संगठनों की कानूनी पहचान को महत्व दें। भू, आवास एवं निर्धनता की समस्याओं के स्थायी समाधान विकसित करने में इन समुदाय संगठनों को वैध एवं महत्वपूर्ण भागीदारों के रूप में मान्यता दें।

4 मुख्य नायक के रूप में समुदाय संगठनों को आवासीय, भू–पट्टेदारी, स्वास्थ्य, कल्याण एवं शिक्षा आधारित सभी सामाजिक या विकास कार्यक्रमों में, शामिल करें।

5 सहयोगपरक् पहल को सुगम बनाएं – निर्धन समुदायों की ज़रूरतों पर सकेंद्रित गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, वास्तुकारों, नागरिक समूहों एवं निजी क्षेत्र के आपरेटरों जैसे अन्य मुख्य शहरी नायकों एवं संगठनों के आपसी सहयोग को बढ़ावा दें।

6 स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों के सृजन को सहयोग दें और ऐसे संस्थानों से नाता जोड़ें जो निर्धनता और आवास से जुड़े सामाजिक एवं आर्थिक विकास में समुदाय संगठनों एवं अन्य सहयोगी संस्थानों की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

7 समुदाय संगठनों की जन संचार साधनों तक पहुँच बनाने में सहायता करें, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन एवं इंटरनेट तक और इन्हें अपने विचारों के प्रसार के नए तरीके प्रदान करें और इनके योगदान को इनके वैयक्तिक समुदायों से परे के अन्य क्षेत्रों एवं समाज के अन्य भागों तक पहुँचाने का प्रयास करें।

8 समुदाय संगठनों एवं इनके परिसंघों एवं नेटवर्कों को लोक प्रशासन सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं विकास में एक सुयोग्य सरकारी साधन के रूप में शामिल करें ताकि गरीबों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ कर, इनकी पूर्ति की जा सकें।

9 अभिव्यक्ति दौरों एवं विनिमय कार्यक्रमों में सहयोग एवं सहभागिता – विभिन्न जगहों में समुदाय संगठनों और समुदाय–चालित सहायता पहल के आपसी सहयोग से विनिमय कार्यक्रमों की शुरूआत करना। सांझे अभिव्यक्ति (एक्सपोज़र) दौरों को लागू करना जिससे समुदाय एवं सरकारी प्रमुख व्यक्ति यह समझ सकें कि आपसी सहयोग से वे शक्तिशाली भागीदारी की शुरूआत कर सकते हैं और सांझे दृष्टिकोण का प्रसार कर सकते हैं।

10 निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरूआत – जिससे ये गरीबों के जीवन यापन की दशाओं से सीधे रूबरू हो सकें और गरीबों के ऐसे सफल नज़रिए को भी आत्मसात कर सकें जिनसे गरीब ऐसी दशाओं से उभर सके हैं।

स्त्रोत : प्लूम्मर, 2000

सन्दर्भ

प्रकाशन

एशियन कोलिशन फार हाऊसिंग राइट्स (ए सी एच आर), 2000 *फेस टू फेसः नोट्स फ्राम द नेटवर्क आन कम्यूनिटी एक्सचेन्ज,* इस प्रकाशन के लिए वेबसाईट www.achr.net से सम्पर्क किया जा सकता है।

एनजोरेना एडुराडो जोर्ज एस जे, 1996 (द्वितीय संस्करण) *हाऊसिंग द पूअरः द एशियन एक्सपीरियेन्स,* पगतम्बयायोंग फाउन्डेशन इन सेबु, फिलिपाईन्स।

एनजोरेना एडुराडो जोर्ज एस जे एण्ड फर्नांडीज, फ्रासिस्को एल. 2004, *हाऊसिंग द पूअर इन द न्यू मिलेनियम,* पगतम्बयायोंग फाऊन्डेशन, सेबु, फिलिपाईन्स।

बिग टी. एण्ड सेट्टरथवेट, डी (eds), 2006, *हाऊ टू मेक पावर्टी हिस्टरी, द सेन्ट्रल रोल आफ लोकल आर्गेनाईजेशन्स इन मीटिंग द एम डीजीएस,* आईआईईडी, लन्डन।

क्रूज सी एण्ड सेट्टरथवेट डी, 2005 *बिल्डिंग होम्स, चेंजिग आफीशियल एप्रोचेसः द वर्क आफ अर्बन पूअर आर्गेनाइजेशन एण्ड देयर फेडरेशन्स एण्ड देयर कन्ट्रीब्यूशन्स टू मीटिंग द मिलेनियम डेवेल्पमेण्ट गोल्स,* पावर्टी रिडक्शन इन अर्बन एरियास सीरीज वर्किंग पेपर 16, आई आई ई डी, मई 2005।

गुजित आई एण्ड कौल शाह एम, 1998य *द मिथ आफ कम्यूनिटी, जेन्डर इशूज़ इन पार्टीसिपेटरी डेवेल्पमेण्ट,* आई टी डी जी पब्लिशिंग, लन्डन।

हसन, आरिफ, 2001, *वर्किंग विद गवर्नमेण्टः द स्टोरी आफ ओ पी पी एस कोलैबोरेशन विद स्टेट एजन्सीज़ फार रेपलिकेटिंग इट्स लो कास्ट सेनिटेशन प्रोग्राम,* सिटी प्रेस, कराची।

हसन आरिफ, (ed) 2001, *कम्यूनिटी इनिशेटिव्स फोर केस स्टडीज फ्राम कराची,* सिटी प्रेस कराची।

हसन आरिफ, 2001 *वर्किंग विद कम्यूनिटीज़,* सिटी प्रेस कराची।

इन्टरनेशनल इनस्टीच्यूट फार एन्वायर्नमेण्ट एण्ड डेवेल्पमेण्ट, (आईआईईडी), 2001, *सिविल सोसायटी इन एक्शनः ट्रांस्फोर्मिंग अपरच्यूनिटीज़ फार द अर्बन पूअर,* स्पेशल इशू आफ एन्वायर्नमेण्ट एण्ड अर्बनाईजेशन आईआईईडी लन्डन यूके वाल्युम 13 नं.1।

प्लूमर जे 2000, *म्यून्सपैलिटीज़ एण्ड कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन, ए सोर्सबुक फार केपिसिटी बिल्डिंग,* अर्थस्कैन लन्डन एण्ड स्टर्लिंग वी ए।

यूएन एस्कैप 1996, *लिविंग इन एशियन सिटीजः द इम्पौन्डिग क्राइसिस, काज़िज, कनसीक्योंसिस एण्ड आल्टरनेटिव्स फार द फ्यूचर,* रिपोर्ट आफ द सेकेन्ड एशिया –पैसिफिक अर्बन फोरम, युनाइटैड नेशन्स, न्यूयार्क, 1996।

यूएन हैबीटैट, 2003, *स्लम्स आफ द वर्ल्डः द फेस आफ द अर्बन पावर्टी इन द न्यू मिलेनियम?* वर्किंग पेपर, नैरोबी।

यूएन हैबीटेट, 2001, *बिल्डिंग ब्रिजिज़ बिटविन सिटीजेनस एण्ड लोकल गवर्नमेण्ट्स थ्रू मैनेजिंग कनफलिक्ट एण्ड डिफरेन्सिस पार्ट–I* ओर *II, नैरोबी।*

वेबसाइट

एशियन कोलिशन फार हाऊसिंग राइट्स (एसीएचआर) www.achr.net

एन्वायर्नमेण्ट एण्ड अर्बनाईजेशन, द जोर्नल आफ द इन्टरनेशनल इन्स्टीच्यूट फार एन्वायर्नमेण्ट एण्ड डेवेल्पमेण्ट (आईआईईडी), लन्डन यू के http://sagepub.com

ओरंगी पायलट प्रोजेक्ट (ओपीपी) www.oppinstitutions.org

सोसायटी फार प्रोमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेन्टर्स (स्पार्क), इन्डिया www.sparcindia.org

सेवान्था एनजीओ कोलम्बो, श्रीलंका www.sevantha.org

स्लम/शैक डवेल्र्स इन्टरनेशनल (एसडीआई) www.sdinet.org

अर्बन रिसोर्स सेन्टर कराची www.urckarachi.org

युनाईटैड नेशन्स इकनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड द पैसिफिक (यूएन एस्कैप) www.unescap.org

हाऊसिंग द अर्बन पूअरः ए प्रोजेक्ट आफ द युनाईटिड नेशन्स इकनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड द पैसिफिक (यूएन एस्कैप) www.housing-the-urban-poor.net

युनाइटैड नेशन्स ह्यूमन सेट्लमेण्ट्स प्रोग्राम www.unhabitat.org

अधिक जानकारी के लिए मुख्य वेबसाइट्स की एक विस्तृत सूची: *इन तत्काल गाईडों की श्रृंखला में चर्चित प्रमुख मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी देने वाली वेबसाइट्स की विस्तृत सूची के लिए 'हाऊसिंग द अर्बन पूअर' वेबसाइट देखें और ''आर्गेनाइजेशन्स डैटाबेस'' तक पहुंचने के लिए लिन्क्स अनुसार चलिये।*

www.housing-the-urban-poor.net

चित्रः यूएसएआईडी फायर प्रोजेक्ट

एशिया एवं प्रशांतीय क्षेत्र में तीव्र शहरीकरण एवं आर्थिक वृद्धि के दबाव से शहरी गरीबों को अपने आवासीय इलाकों से निष्कासित किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में इनका पुनर्वास रोज़गार एवं आर्थिक अवसरों से दूर परिधीय क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही, 50 करोड़ से अधिक लोग फिलहाल एशिया एवं प्रशांतीय क्षेत्र की स्लम या और अनाधिकृत बस्तियों रह रहे हैं और यह संख्या बढ़ रही है।

स्थानीय सरकारों को वर्ष 2020 तक स्लमवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने पर लक्षित 'मिलेनियम विकास लक्ष्य' की प्राप्ति की दिशा में पहले कदम के रूप में शहरी गरीबों के आवासीय अधिकरों की रक्षा के लिए नीति प्रपत्र चाहिएं। इन तत्काल गाइडों का उद्देश्य 'शहरी गरीबी घटाने' के ढाँचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर गरीबों के आवास और शहरी विकास के पक्ष में नीति निर्माताओं द्वारा समझ को प्रौन्नत करना है।

इन तत्काल गाइडों में निम्नलिखित आवास सम्बन्धी मुद्दों से निपटने से सम्बन्धित प्रवृतियों और परिस्थितियों, संकल्पनाओं, नीतियों, साधनों और सिफारिशों का समीक्षात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित करके सहज पठनीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये मुद्दे हैंः

(1) **शहरीकरणः** शहरी विकास में गरीबों की भूमिका, (2) **न्यून आय-आवासः** शहरी गरीबों को समुचित आवास ढूँढनें में सहायता देने के तरीके, (3) **भूमिः** शहरी गरीबों के आवास हेतु एक निर्णायक तत्व, (4) **निष्कासनः** शहरी गरीब समुदायों को पूरी तरह नष्ट करने के विकल्प (5) **आवासीय वित्तः** आवास खरीदने हेतु गरीब की सहायता करने के तरीके, (6) **समुदाय-आधारित संगठनः** गरीब, विकास के एजेंट के रूप में, (7) **किराये के आवासः** गरीबों के लिए अति उपेक्षित आवासीय विकल्प।

यह तत्काल गाइड 6 इस बात का परीक्षण करती है कि जब अपनी आवासीय समस्याओं के सफल समाधान खोजने की बात आती है तो ये समुदाय संगठन कितने मूल्यवान और साधन सम्पन्न हो सकते हैं। यह गाईड इस बात पर भी दृष्टि डालती है कि एशिया में समुदाय संगठन कैसे विकसित हुए, कैसे कार्य करते हैं, और नीति निर्माताओं के लिए, विशेषतया विकेन्द्रीकरण के सन्दर्भ में उपयोगी किन साधनों का प्रयोग करते है।

अधिक जानकारी-वेबसाइट www.housing-the-urban-poor.net से प्राप्त की जा सकती है।

युनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सैट्लमेण्ट्स प्रोग्राम (यूएन हैबीटैट)
पो.आ. बाक्स 30030 जी.पी.ओ 00100
नैरोबी, केन्या
फैक्स: (254-20) 7623092 (TCBB Office)
ई.मेल: tcbb@unhabitat.org
वेबसाइट: www.unhabitat.org

युनाइटेड नेशन्स इकनामिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पेसिफिक (यून एस्कैप)
राजदमनेरन नोक एवेन्यू, बैंकाक 10200, थाईलैण्ड
फैक्स: (66-2) 288 1056/1097
ई.मेल: escap-prs@un.org
वेबसाइट: www.unescap.org